सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 263, नई दिल्ली । मंगलवार, 03 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 ईपीएफओ की माफी योजना 2024 को मंजूरी

06 डिजिटल युग में स्त्री सशक्तीकरण

08 सच है, यह सरकार नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन है जिसने आलू मनाया है

## एक घंटे का सफर 20 मिनट में: केंद्र ने ग्रीनफील्ड पठानकोट हाईवे के लिए दिए 666.81 करोड़, जम्मू वालों को भी फायदा

संजय बाटला

पंजाब में ग्रीनफिल्ड हाईवे के लिए केंद्र ने 66 .81 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। इस हाईवे से सफर आसान होगा। ग्रीनफील्ड पठानकोट लिंक रोड बनने से एक घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा।

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने पंजाब में ग्रीनफील्ड पठानकोट लिंक रोड के निर्माण के लिए 666.81 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 12.34 किलोमीटर लंबी यह सड़क एनएच-44 पर स्थित तलवाड़ा जट्टां गांव को दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर स्थित गोबिंदसर गांव से जोड़ेगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर की तरफ जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। मौजूदा रूट को 53 किलोमीटर से 37 किलोमीटर तक सुव्यवस्थित करने से लिंक रोड के जरिये यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। गडकरी ने लिखा कि हमने हाईवे के लिए राशि मंजूर कर दी है। इस हाईवे के बनने के बाद लोगों के समय और रुपये दोनों में ही बचत होगी। क्योंकि एक घंटे का सफर महज 20 मिनट में पूरा हो जाएगा।

यह जानकारी लोकसभा गुरदासपुर के उम्मीदवार पूर्व डिप्टी स्पीकर और पूर्व विधायक दिनेश बबू ने गांव भंनवाल में दी। इस मौके पर दिनेश सिंह बबू ने कहा कि पंजाब में ग्रीनफील्ड पठानकोट हाईवे के लिए 666.81 करोड़ मंजूर हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। पठानकोट के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा।

दिनेश बबू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर जाने वाले लोगों को इस हाईवे के बनने से भरपूर फायदा मिलेगा। इस हाईवे के बनने से 1 घंटे का सफर 20 मिनट में होगा। इस मौके पर मंडल महासचिव बलविंदर सिंह मक्खन अवतार सिंह कोहाल ज्ञान सिंह कमल सिंह आदि उपस्थित थे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

## प्रदेश में 1.39 लाख करोड़ की लागत से बनेंगे नए हाईवे सड़कों को त्वरित गति से दी जाएगी जमीन

परिवहन विशेष न्यूज

यूपी में आने वाले समय में हाइवे का जाल बिछने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से संबंधित काम युद्धस्तर पर पूरे करने के निर्देश दिए।

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में 1.39 लाख करोड़ रुपये की लागत से नए हाईवे बनेंगे। इसके लिए शीघ्र ही विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होगी। साथ ही महाकुंभ से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग, बाईपास, इनर रिंग रोड और पुल निर्माण के काम भी 25 दिसंबर तक पूरे करने होंगे। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए। सीएम के सरकारी आवास पर शनिवार को हुई इस बैठक में प्रयागराज महाकुंभ-2025 से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों और सड़क परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश में नई सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बरेली में एनएच 530बी के सुदृढ़ीकरण, प्रतापगढ़ जिले में एक बाईपास, प्रयागराज-दोहरीघाट मार्ग को दो लेन से चारलेन करने, बाराबंकी-जरवल-बहराइच मार्ग (एनएच 927) के निर्माण, कबरई-कानपुर कॉरिडोर के निर्माण के संबंध में डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि शामली-गोरखपुर कॉरिडोर और अलीगढ़-मुरादाबाद-बिजनौर कॉरिडोर की बिड आ गई है, जबकि अयोध्या (उतरौला)-प्रयागराज के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए बिड आमंत्रित की गई है। प्रयागराज-वाराणसी-आरा-पटना कॉरीडोर के लिए भी बिड आमंत्रित की गई है। गोरखपुर-जमनिया-सैयदराजा कॉरीडोर और गोरखपुर-किशनगढ़-सिलीगुड़ी कॉरीडोर के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

**ये काम युद्धस्तर पर करें पूरा**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से संबंधित काम युद्धस्तर पर पूरे करने के निर्देश दिए। इन निर्माण कार्यों में 63.17 किमी रायबरेली से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य, चार स्थानों पर फोरलेन बाईपास के निर्माण, 7.6 किलोमीटर प्रयागराज इनर रिंग रोड (प्रथम चरण, पैकेज-थर्ड), 10.98 किमी दो लेन प्रतापगढ़ बाईपास, 5.10 किमी फोरलेन जसरा बाईपास और 24.2 किलोमीटर प्रयागराज फाफामऊ में गंगा पर बने सेतु के समानांतर नए 6-लेन सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (रायबरेली से प्रयागराज खंड) में चार स्थानों-जगतपुर, बाबूगंज, ऊंचाहार व आलापुर पर निर्माणाधीन बाईपास में से दो पूर्ण हो चुके हैं, शेष दो को भी समय से पूरा करा लिया जाए। राष्ट्रीय राजमार्गों में हर 20 किमी पर एंबुलेंस व रिकवरी व्हीकल और पेट्रोलिंग वाहन व क्रेन की व्यवस्था की जाए।

**सड़कों के लिए तेजी से भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश**

सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी नजदीकी अस्पतालों की मैपिंग होनी चाहिए। सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। महाकुंभ जाने वाले मार्गों पर टोल प्लाजा के पास अतिरिक्त शौचालय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेयजल सुविधाएं, चिकित्सा एवं यातायात सहायता पोस्ट की व्यवस्था कराई जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढा मुक्त हों। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में नए राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तेजी से पूरी की जाए।

**लखनऊ-गाजीपुर हाईवे की होगी मरम्मत**

मुख्यमंत्री ने लखनऊ-गोरखपुर, बांदा-कानपुर और गाजीपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत की आवश्यकता बताई। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को इन सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धार्थनगर के नौगढ़ से शोहरतगढ़ होते हुए तुलसीपुर (बलरामपुर) तक के मार्ग का सुदृढ़ीकरण जरूरी है, जिस पर सहमति जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

**बहराइच-श्रावास्ती समेत 10 जिलों में बनेंगे बाईपास**

नितिन गडकरी ने अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मिर्जापुर व सहारनपुर मंडल में रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 बाईपास निर्माणधीन हैं। प्रदेश के 10 जिलों औरैया, बुलंदशहर, मैनपुरी, बहराइच, बागपत, भदोही, संभल, कौशाम्बी, चंदौली और श्रावस्ती में बाईपास बनाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने गोरखपुर-शामली व कानपुर-गाजियाबाद मार्ग के डीपीआर शीघ्र बनाने के निर्देश दिए।

**ये भी रहे मौजूद**

इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, पीडब्ल्यूडी राज्यमंत्री बृजेश सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव वन अनिल कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह, सलाहकार मुख्यमंत्री अवनीश कुमार अवस्थी भी उपस्थित रहे।

## 80 ई-बसों ने बचाया 25.45 लाख लीटर डीजल, पर्यावरण के लिए भी फायदा, अब बेड़ा बढ़ाकर 438 करेगा सीटीयू

80 ई-बसों ने न केवल लाखों लीटर डीजल बचाया है, बल्कि वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम किया है। 6719 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की रोकथाम ने शहर की वायु गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। ई-बसों का संचालन पर्यावरणीय लाभ के साथ-साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद साबित हो रहा है।

**चंडीगढ़।** चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की मौजूदा 80 ई-बसों ने अब तक 25.45 लाख लीटर डीजल की बचत की है और साथ ही 6719 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोका है। विभाग को आर्थिक बचत भी हो रही है। इसलिए सीटीयू ने 2026-27 तक इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को 80 से बढ़ाकर 438 करने का लक्ष्य रखा है। हर साल के लिए लक्ष्य तय किया गया है। विभाग के अधिकारियों का दावा है कि अगले कुछ महीनों में सीटीयू को 100 ई-बसें मिल सकती हैं। इसके लिए एक कंपनी से समझौता भी हो चुका है। डीजल पर होने वाले खर्च में कमी से परिवहन विभाग को आर्थिक बचत हो रही है। सीसीबीएसएस के राजस्व में वर्ष 2021-22 से अब तक लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वर्ष 2021-22 में सीसीबीएसएस ने साल भर में जितनी कमाई की थी, वर्ष 2024-25 में पहली तिमाही में ही करीब उतने रुपये कमा लिए हैं। इसके अलावा, ई-बसें अपेक्षाकृत कम मेंटेनेंस की मांग करती हैं, जिससे परिचालन लागत कम होती है। सीटीयू ने 2026-27 तक अपने इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को 438 तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत इस साल चंडीगढ़ में 100 और अगले साल 170 नई ई-बसें शामिल करने की योजना है।

**अगले चार-पांच महीने में आ सकती हैं 100 ई-बसें**

सीटीयू ने 12 मीटर की अल्ट्रा लो फ्लोर की 100 ई-बसों के लिए पीएमआई के साथ समझौता किया है। यह बसें डिपो नंबर-4 के 100 डीजल बसों की जगह लेंगी। किलोमीटर के आधार पर बसें चलाई जाएंगी, जिसके लिए सीटीयू 61.80 रुपये चुकाएगा। इसमें केंद्र सरकार से प्रति किमी 24 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान में शहर की सड़कों पर जो 80 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं, वो केंद्र सरकार की फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत लाई गई हैं। प्रति बस केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को 45 लाख रुपये की सब्सिडी दी है लेकिन अब सब्सिडी देने के मॉडल को बदला गया है। अब प्रति किमी 24 रुपये की सब्सिडी केंद्र देगा। वर्तमान में 40-40 करके 80 ई-बसों के लिए दो कंपनियों से समझौता हुआ है।

## एप के माध्यम से ई रिक्शा व ऑटो बुक कर सकेंगे श्रद्धालु, चलेगी पिंक टैक्सी, महिलाएं होंगी ड्राइवर

परिवहन विशेष न्यूज

महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सरकार की ओर से इन श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने के लिए 7000 से अधिक रोडवेज बसों और 550 शटल बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है, जबकि रेलवे भी करीब 1000 अतिरिक्त ट्रेनों के साथ ही कुल तीन हजार ट्रेनें चलाने जा रहा है।

**नई दिल्ली।** महाकुंभ मेला 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी परिवहन के साथ-साथ निजी परिवहन सेवा प्रदाता भी पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ओला और उबर की तर्ज पर एप के माध्यम से ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा का भी लाभ मिलने जा रहा है।

इन ई व्हीकल्स के ड्राइवर्स पूरी तरह प्रशिक्षित और व्यवहार कुशल होंगे। साथ ही इसमें पिंक टैक्सी की भी सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें महिलाएं चालक होंगी। सबसे खास बात कि श्रद्धालुओं को मनमाना किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से छुटकारा मिलेगा। 15 दिसंबर से श्रद्धालु और पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। महाकुंभ से पहले इस तरह की पहल से श्रद्धालुओं को न सिर्फ सुविधाजनक और सस्ती लोकल राइड का लाभ मिलेगा, बल्कि योगी सरकार के ग्रीन महाकुम्भ की अवधारणा को भी समर्थन मिलेगा।

**चालकों को दिया जा रहा है अच्छे व्यवहार का प्रशिक्षण**

महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सरकार की ओर से इन श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने के लिए 7000 से अधिक रोडवेज बसों और 550 शटल बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है, जबकि रेलवे भी करीब 1000 अतिरिक्त ट्रेनों के साथ ही कुल तीन हजार ट्रेनें चलाने जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज में श्रद्धालुओं को लोकल ट्रांसपोर्ट की कमी न हो, इसके लिए यूपी के स्टार्टअप कॉम्फी ई मोबिलिटी ने ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

15 दिसंबर से शुरू हो रही इस सेवा में श्रद्धालु लोकल राइड के लिए ई व्हीकल्स को चुन सकेंगे। खास बात ये है कि सभी ड्राइवरों को अगंतुकों से अच्छा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जिन श्रद्धालुओ को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिक्कत है, उनकी सुविधा के लिए सभी ड्राइवरों को गूगल वॉइस असिस्टेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यह ई व्हीकल्स रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा एवं सभी होटलों से आराम से उपलब्ध हो सकेंगे। इसमें महिला ड्राइवर के साथ पिंक सेवा का भी प्रावधान है। शुरुआत में 30-40 पिंक टैक्सी सुविधा प्रदान करने के लिए अवेलबल होंगी।

**पर्यावरण अनुकूल होगी सुविधा**

कॉम्फी ई मोबिलिटी की फाउंडर और डायरेक्टर मनु गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ मेले में देश और विदेश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुविधाजनक, सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी एप आधारित ई रिक्शा टैक्सी सेवा प्रदान की जाएगी। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा देने के साथ ही सस्ती राइड उपलब्ध कराने के लिए किसी भी ड्राइवर से कमीशन नहीं लिया जाएगा। सुरक्षित राइड के लिए प्रत्येक ड्राइवर और व्हीकल के ओनर का वेरिफिकेशन कराया गया है।

300 ई रिक्शा के साथ पूरे प्रयागराज एवं कुंभ मेला में इसकी शुरुआत की जा रही है। सभी ड्राइवर्स को आगंतुकों के साथ अच्छे व्यवहार की ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी ई रिक्शा और ऑटो जीपीआरएस सिस्टम से ट्रैक किए जाएंगे, जबकि यह पूरी तरह फिट और कवर्ड भी होंगे। इसका किराया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगा, जो प्रति किमी. के हिसाब से निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा किराया वसूलने वाले रिक्शा चालकों से भी मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह की असुविधा होने पर श्रद्धालु कॉल सेंटर पर शिकायत भी कर सकेंगे।

**श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनेगा महाकुम्भ**

सीईओ आरके चौहान ने बताया कि कॉम्फी ई मोबिलिटी स्टार्टअप इंडिया से मान्यता प्राप्त है। हमारा उद्देश्य अर्बन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रस्तुत कर वायु प्रदूषण को कम करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ से इसकी शुरुआत की जा रही है, ताकि इस महापर्व को लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बनाया जा सके। महाकुंभ 2025 में पूरे विश्व से सनातनियों के अलावा विभिन्न समुदाय के लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े अनुष्ठान को देखने और समझने के लिए प्रयागराज आएंगे। वह यहां महाकुंभ के मंथन से निकलने वाले पर्यावरण संरक्षण के संदेश, यहां की संस्कृति एवं अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। इस आयोजन के बाद इस पहल को हम प्रदेश के अन्य शहरों में लेकर जाएंगे।

# क्यों अपने दोस्त को दूसरे दोस्तों से मिलाने में हिचक रहीं महिलाएं, आखिर क्या है Friend Hoarding का नया ट्रेंड?

अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने दोस्तों को एक-दूसरे से मिलाना नहीं चाहती हैं। वे अपने दोस्तों को सिर्फ अपने लिए रखना चाहती हैं। इसे दोस्तों को जमा करना यानी Friend Hoarding कहा जाता है। इस ट्रेंड पर स्टडी करने वाली डेनिएल बेयार्ड जैक्सन कहती हैं कि ऐसा (Why Women Dont Introduce Friends) इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं डरती हैं कि कहीं उनके दोस्त उनसे दूर न चले जाएं।

**नई दिल्ली।** अमेरिका में हाल के वर्षों में एक नया चलन देखने को मिला है जिसे फ्रेंड होर्डिंग (Friend Hoarding) कहा जाता है। इस चलन में लोग अपने दोस्तों को एक-दूसरे से मिलने से बचते हैं। बिजी लाइफस्टाइल के इस दौर में लोग अपने दोस्तों को एक पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह मानने लगे हैं। इस विषय से जुड़े एक्सपर्ट्स की मानें, तो 'फ्रेंड होर्डिंग' का बढ़ना असुरक्षा और दोस्तों को खोने के डर से जुड़ा है और यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखा जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

**क्या है फ्रेंड होर्डिंग?**

'फ्रेंड होर्डिंग' एक ऐसा चलन है जिसमें लोग जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्त बना लेते हैं। एक्सपर्ट की मानें, तो दोस्ती में असुरक्षा होना एक सामान्य मानवीय भाव है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ावा दिया है। इंटरनेट ने लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम किया है, लेकिन साथ ही इसने लोगों को अलग-थलग भी कर दिया है। आज लोग अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और इंटरनेट पर विभिन्न समूहों से जुड़े होते हैं। इस अलगाव ने लोगों में एक तरह का सामूहिक अकेलापन पैदा कर दिया है। 'फ्रेंड होर्डिंग' इसी अकेलेपन से बचने की एक कोशिश है।

**अकेलेपन का शिकार हो रहे लोग**

अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में अकेलापन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, हर तीसरा अमेरिकी नागरिक अकेलेपन का अनुभव करता है। यह समस्या युवाओं में खासतौर से चिंताजनक है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 39% अविवाहित वयस्कों ने स्वीकार किया कि वे हर हफ्ते अकेलेपन की भावना से जूझते हैं, जबकि विवाहित व्यक्तियों में यह आंकड़ा 22% है।

**क्यों डरते हैं हम अपने दोस्तों को मिलाने से?**

कई बार लोग अपने दोस्तों को एक-दूसरे से मिलाने में हिचकिचाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनके नए दोस्त उनके पुराने दोस्तों के इतने करीब न हो जाएं कि वे उन्हें पीछे छोड़ दें। इस भावना को मनोविज्ञान में 'दोस्ती में जलन' कहा जाता है। इसके अलावा, लोगों की अपनी पहचान को लेकर भी उलझन होती है। हम अलग-अलग दोस्तों के साथ अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जब इन दोस्तों को एक साथ लाने की बात होती है, तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारी यह अलग-अलग पहचान खत्म न हो जाए।

**दोस्ती पर सोशल मीडिया का असर**

सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दोस्ती के तरीके को बदलकर रख दिया है। आजकल लोग ज्यादातर निजी दोस्ती में विश्वास करते हैं। हालांकि, इस तरह की दोस्ती के कुछ नुकसान भी हैं। एक दोस्त को दूसरे दोस्तों से मिलवाने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। इससे एक ऐसा समूह बनता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता है। दोस्तों के बीच का यह जुड़ाव हमें सुरक्षित महसूस कराता है और हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है।

# पड़ोसी के साथ रहता है आए-दिन का क्लेश, तो रिश्तों में मधुरता लाएंगे 5 टिप्स; सोसाइटी में सब करेंगे आपकी तारीफ

क्या आप जानते हैं कि मुसीबत के समय सबसे पहले कौन मदद के लिए आगे आता है? ज्यादातर लोग अपने पड़ोसी का नाम लेंगे लेकिन ये रिश्ता आखिर कैसे बनाया जाता है? आइए जानते हैं कि आप अपने पड़ोसियों के साथ कैसे अपने रिश्तों को मधुर बनाए रख सकते हैं और किसी भी तरह के झगड़े से कैसे बच सकते हैं।

**नई दिल्ली।** पड़ोसियों के बीच छोटी-मोटी अनबन होना आम बात है, लेकिन ये मतभेद अगर लंबे समय तक बने रहें तो हमारी जिंदगी में अशांति पैदा कर सकते हैं। इसलिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी ये मतभेद दूर हो जाएं और रिश्ते दोबारा मधुर (Improve Neighbor Relations) बन जाएं, उतना ही अच्छा होता है। अगर आप भी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं या उनके साथ किसी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम आपको इससे जुड़े कुछ खास टिप्स (Tips For Better Neighbor Relationships) शेयर करने जा रहे हैं।

**कुछ बातों को अनदेखा करें**

छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करने से अक्सर तनाव बढ़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, खासकर जब बात हमारे पड़ोसियों की हो। अगर वे अनजाने में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें परेशानी होती है, तो शांति से इस बात को समझने की कोशिश करें। सहनशीलता और समझदारी से आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।

**बातचीत से बेहतर कुछ नहीं**

बातचीत का रास्ता अपनाना सबसे बेहतर समाधान है। जब भी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो, तो गुस्सा करने के बजाय शांति से बैठकर बातचीत करें। एक-दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें, अपनी भावनाओं को खुलकर बयां करें और मिलकर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें। इस तरह की बातचीत से न सिर्फ आपकी गलतफहमियां दूर होंगी बल्कि आपका रिश्ता भी मजबूत होगा।

**मिलकर फैसले लें**

आपसी बातचीत ही है जो हमारी सोसाइटी को एक खुशहाल जगह बना सकती है। कोई भी समस्या हो, मिलकर बैठकर उसका हल निकालें। इससे न सिर्फ समस्या का हल निकलेगा बल्कि पड़ोसियों के बीच का रिश्ता भी मजबूत होगा। जब सभी मिलकर फैसले लेंगे तो सभी को वो फैसला मंजूर होगा और एक शांतिपूर्ण माहौल बनेगा।

**एक-दूसरे को सपोर्ट करें**

आपसी सहयोग से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए अगर पड़ोसी को किसी के मदद की जरूरत हो तो आप आगे आएं। चाहे किसी बीमार को खाना पहुंचाना हो या छोटे-मोटे घरेलू काम में उनकी मदद करनी हो।

**बाउंड्री बनाकर रखें**

अपने पड़ोसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है। बार-बार उनके घर जाना या उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना आपसी रिश्तों को खराब कर सकता है। उन्हें प्राइवेसी निजता देने से आपसी संबंध मधुर रहेंगे। अगर आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो उनकी निजी जिंदगी में दखल देने से बचें। उन्हें अपनी मर्जी से जीने दें।

# विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश को लगाएं केले की खीर का भोग, बेहद आसान है रेसिपी

विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इस दिन भक्तगण गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि गणेश जी को पीला रंग बेहद प्रिय है इसलिए इस खास मौके पर केले की खीर बनाकर उन्हें भोग लगाना काफी शुभ है। खास बात है कि केले की खीर को बनाना भी बेहद आसान है।

**नई दिल्ली।** हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है और इस साल यह 5 दिसंबर को है। इस पावन अवसर पर भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही अन्य देवताओं की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इस शुभ अवसर पर आप भगवान गणेश को केले की स्वादिष्ट खीर का भोग (Banana Kheer for Lord Ganesha) लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि।

**केले की खीर बनाने के लिए सामग्री**

1 लीटर दूध
3-4 पके हुए केले (मैश किए हुए)
1/4 कप चीनी (स्वादानुसार)
10-12 केसर के धागे
1/2 चम्मच इलायची पाउडर
1/4 कप कटे हुए बादाम और काजू (सजाने के लिए)

**केले की खीर बनाने की विधि**

सबसे पहले एक मोटे तले वाले पैन में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबाल लें। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध नीचे लग न जाए।

इसके बाद एक छोटे बर्तन में केसर के धागे को गर्म दूध में भिगो दें। इससे केसर का रंग और स्वाद दूध में अच्छे से घुल जाएगा।

फिर जब दूध उबलने लगे तो इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।

अब मैश किए हुए केले को दूध में डालकर अच्छी तरह मिला लें। तब तक पकाएं जब तक कि केले दूध में पूरी तरह से मिल न जाएं और खीर गाढ़ी न हो जाए।

इसके बाद गैस बंद कर दें और खीर को थोड़ा ठंडा होने दें। ऊपर से कटे हुए बादाम और काजू से सजाकर भगवान गणेश को भोग लगाएं और फिर प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें।

**स्पेशल टिप्स**

आप चाहें तो केले को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर भी डाल सकते हैं।

आप अपनी पसंद के अनुसार दूध की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं।

चीनी की मात्रा को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य मेवों जैसे पिस्ता, मखाने आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

इलायची के अलावा आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य मसालों जैसे जायफल, दालचीनी आदि का भी यूज कर सकते हैं।

# पार्टी के बाद अपनी त्वचा को डिटॉक्स कैसे करें, इन 7 टिप्स को फॉलो कीजिए

जब हम सभी किसी पार्टी में जाते हैं तो हैवी मेकअप जरुर करते जाते हैं। भारी मेकअप देर रात त्वचा में लगा रहता है। पार्टी में ज्यादा खाना खाने से आपकी त्वचा भी काफी सुस्त पड़ सकती है। ऐसे में आपके चेहरे को डिटॉक्स करना भी जरुरी होता है। आइए जाने कैसे करें चेहरे को डिटॉक्स।

**नई दिल्ली।** पार्टियां करना आखिर किस को पसंद नहीं है। हम सभी लेट नाइट पार्टियां या नॉर्मल पार्टी में जरुर जाते हैं। जहां अपने चेहरे पर काफी मेकअप करके जाते हैं। भारी मेकअप चेहरे पर देर रात तक रहना और पार्टी का स्वादिष्ट भोजन खाने से आपकी त्वचा एकदम सुस्त, थकी हुई बन जाती है, जो डिटॉक्स की जरूरत वाली दिखने लगती है। आइए जानते हैं किस तरह से अपने चेहरे को डिटॉक्स कर सकते हैं।

**हाइड्रेशन जरुरी है**

अपने चेहरे को हाइड्रेट करने के लिए खूब पानी पिएं और शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कैमोमाइल जैसी हर्बल टी का सेवन जरुर करें। हाइड्रेशन के लिए खूब पानी पिएं।

**चेहरे के लिए डबल सफाई जरुरी**

जब किसी पार्टी से लौटकर आते हैं, तो केवल माइसेलर पानी और मेकअप वाइप्स पर निर्भर न रहें। मेकअप को हटाने के लिए क्लींजिंग ऑयल या बाम से शुरुआत करें। इसके बाद चेहरे के बैक्टीरिया साफ करने के लिए आप सौम्य क्लींजर से फेस को क्लीन करें।

**डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क इस्तेमाल करें**

चेहरे की अशुद्धियां निकालने के लिए और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए सप्ताह में दो बार मिट्टी या चारकोल मास्क लगाएं। चेहरे के रोमछिद्रों को क्लीन करने के लिए 10-15 मिनट तक डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क लगाएं। फिर चेहरे को साफ पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा मुलायम हो जाएगी।

**सनस्क्रीन जरुर लगाएं**

सनस्क्रीन लगाने से काले-धब्बे और पिगमेंटेशन को रोकता है। सनस्क्रीन लगाने से आपकी त्वचा चमकदार बनती है और पार्टी के लिए भी तैयार रहती है।

**आईस फेशियल करें**

अपने चेहरे पर ठंडे टी बैग्स या खीरे से देर रात की सूजन को कम करने के लिए और सर्कुलेशन को बढ़ावा देने के लिए चेहरे की मालिश करें। जिससे त्वचा तरोताजा हो जाएगी। आप बर्फ टुकड़े थोड़ी देर रखकर उस पानी से चेहरे को धो सकते हैं या फिर सिकाई कर सकते हैं।

**नींद को प्राथमिकता दें**

अच्छी त्वचा के लिए चेहरे की मरम्मत के लिए नींद लेना भी काफी जरुरी है। अपनी त्वचा को प्राकृतिक रुप से पुनर्जीवित करने में मदद के लिए बढ़िया आराम से सोएं।

**सौम्य एक्सफोलिएशन जरुरी**

मृत कोशिकाओं को हटाने और ब्रेकआउट से बचने के लिए पार्टी के एक या दो दिन बाद हल्के एक्सफोलिएंट का उपयोग करें, जिससे आपकी त्वचा चिकनी और चमकदार हो जाएगी।

# रात को खांसी आपको सोने नहीं देती, तो इन घरेलू उपाय को फॉलो करें

अगर आपको भी रात को खांसी आती हैं, तो सोने से पहले हल्दी का साथ शहद का सेवन करें। हल्दी और शहद दोनों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल व एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं।

सर्दियों की शुरुआत अपने साथ सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं लेकर आती है। कुछ लोगों की खांसी रात में बदतर हो जाती है, जिससे सोना मुश्किल हो जाता है और अगले दिन उन्हें थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। यदि आपको बदलते मौसम के साथ रात में खांसी बढ़ जाती है, तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन घरेलू उपायों से खुद की खांसी को रोकने में मदद कर सकते हैं।

**रात के समय खांसी के लिए आयुर्वेदिक इलाज**

- अगर आपको रात को खांसी होती है, तो आप सोने से पहले हल्दी के साथ शहद का सेवन करने का प्रयास जरुर करें। ये दोनो ही एंटीफंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। आपको हल्दी और शहद एक साथ लेने से खांसी में आराम मिलेगा।

**शहद और हल्दी की ड्रिंक कैसे बनाएं**

- शहद और हल्दी का सेवन करने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी को उबाल लें। उबले हुए पानी में दो चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। ध्यान रहे कि ज्यादा गर्म पानी में शहद मिलाने से बचें, क्योंकि शहद को उच्च तापमान के संपर्क में लाने से इसके लाभकारी गुण कम हो सकते हैं। मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं, छान लें और चाय की तरह इसका आनंद लें।

**शहद और हल्दी के घरेलू उपचार के फायदे**

यह ड्रिंक आपके मुंह के छालों को शांत कर सकता है और सर्दियों में इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह खांसी और सर्दी के लक्षणों को कम करने के लिए एक प्रभावी घरेलू उपचार है।

**अन्य घरेलू उपचार**

- जब आप सोते हैं तो उससे पहले नमक के पानी से गरारे करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी।

- नींबू और शहद का मिश्रण रात के समय खांसी से राहत दिला सकता है, लेकिन बच्चों को यह न दे।

- भुनी हुई अदरक गले की खराश से राहत दिला सकती है और खांसी को कम कर सकती है।

- हल्दी वाला दूध सबसे बेहतरीन उपायो में से एक है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो छींक को कम करने और बेहतर नींद को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

# एनसीवेब के JMC केंद्र की 500 से अधिक छात्राएं पिछले साल हुई थीं फेल, अब जांच के दिए गए आदेश

सुषमा रानी

दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीवेब) के जीसस एंड मैरी कॉलेज (जेएमसी) केंद्र की 500 से अधिक छात्राओं को पिछले वर्ष गलती से फेल कर दिया गया था। छात्राओं ने रविवार और सोमवार को कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। अब परीक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

**नई दिल्ली।** दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीवेब) के जीसस एंड मैरी कॉलेज (जेएमसी) केंद्र की 500 से अधिक छात्राओं को पिछले वर्ष फेल कर दिया गया था। मामले का हल न निकलने पर छात्राओं ने रविवार और सोमवार को कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। अब परीक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।

एनसीवेब की जीएमसी केंद्र में पढ़ रही एक छात्रा विधि ने बताया कि पिछले साल एक साथ सैकड़ों छात्राओं की ईआर (एसेंशियल रिपीट) लगा दी गई। जो पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि जो नंबर हमें भेजे गए थे, उनमें हम पास थे। इसके बाद कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की। उन्होंने परीक्षा विभाग में शिकायत करने को कहा।

**खामी को नहीं किया गया ठीक**

छात्राएं परीक्षा विभाग में मिलकर आईं, लेकिन मामला नहीं सुलझा। कॉलेज की ओर से आश्वासन दिया गया कि खामी को सही कर लिया जाएगा, पर इसे सही नहीं किया गया। अब 30 नवंबर को तीसरे सेमेस्टर के साथ ईआर के पेपरों के फार्म भरने को कॉलेज प्रशासन से छात्राओं को आदेश दिए गए।

**पेपर के अलग से रुपये देना संभव**

छात्रा ने कहा, एक पेपर का फॉर्म भरने में 300 रुपये तक खर्च होते हैं। एनसीवेब में निम्न मध्यम परिवार के छात्राएं पढ़ने आती हैं। उनके लिए हर पेपर के लिए अलग से रुपये देना भी संभव नहीं है। जब छात्राओं की कोई गलती नहीं है, तो वे अलग से ईआर के पेपरों की परीक्षा क्यों दे।

**कॉलेज की लापरवाही की होगी जांच**

डीयू परीक्षा विभाग के ओएसडी प्रो. गुरप्रीत टूटेजा ने कहा, पिछले साल काफी छात्राओं की परेशानी को ठीक किया गया था। कॉलेज की ओर से लापरवाही की जा रही है और मामले में हम जांच कराएंगे। एनसीवेब की निदेशक प्रो. गीता भट्ट ने कहा, कॉलेज की ओर से गलत नंबर भेजे गए थे। इस वजह से ईआर आई थी।

छात्राओं की समस्या को सुलझाया जा रहा है। कॉलेज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डीयू अकादमिक परिषद की

सदस्य डॉ. माया जॉन ने कहा, जीसस एंड मैरी कॉलेज के एनसीवेब सेंटर के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी डीयू में एक बड़े संस्थागत संकट को उजागर करती है।

डीयू में इस तरह की घटनाएं बार-बार होती रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि डीयू कार्यकारी परिषद ने पहले भी विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओपन लर्निंग जहां बड़ी संख्या में पत्राचार मोड के छात्र पढ़ते हैं, उसके लिए एक अलग परीक्षा शाखा बनाने का प्रस्ताव रखा है।

इसी तरह, डीयू के एनसीवेब केंद्रों को एक अलग परीक्षा शाखा के तहत लाया जाना चाहिए। साथ ही, इन केंद्रों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हालांकि, इस तरह की बार-बार होती घटनाओं से ऐसा साफ प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे जरूरी कदम उठाने के लिए इच्छुक नहीं है।

**एबीवीपी ने किया प्रदर्शन**

जेएमसी में एनसीवेब की छात्राओं के परीक्षा परिणामों में आई अनियमितता के कारण छात्राओं को फार्म भरने संबंधित विभिन्न समस्या को लेकर एबीवीपी और डूसू पदाधिकारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन किया। फार्म भरने के लिए पोर्टल को फिर से खोलने की मांग की है। प्रदर्शन में डूसू के उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और सचिव मित्रविंदा करनवाल शामिल रहे।

## अपराधियों के खिलाफ शिकायत करने वालों को ही उल्टा उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है - संजय सिंह

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में नोटिस देकर दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर रोज गैंगवार, गैंगरेप, हत्या, लूट की घटनाएं हो रही हैं और व्यापारियों से अवैध वसूली हो रही है। अपराधियों की शिकायत करने वालों को ही उल्टा जेल में डाल दिया जा रहा है। "आप" विधायक को गिरफ्तार करा कर अमित शाह ने संदेश दिया है कि अपराधियों और माफियाओं के ऊपर उनका हाथ है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि हमने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर पहले भी नोटिस दिया था। आज फिर मैंने 267 का नोटिस दिया है। मैं चहता हूं कि दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए। यहां रोज गैंगवार, गैंगरेप, हत्या, लूट की घटनाएं हो रही हैं। व्यापारियों से अवैध वसूली हो रही है। जो शिकायत कर रहा है, पांच बार शिकायत करने वाले एक विधायक को उल्टा उठाकर अंदर कर दिया गया। मुझे लगता है कि अमित शाह ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि गैंग्स्टर्स, अपराधियों और माफियाओं के ऊपर उनका हाथ है और वो दिल्ली में अपराध बढ़ाने का काम करेंगे, रोकने का नहीं।

## काम पूरा होने के बाद ROB में 2-3 महीने में आई दरार दिल्ली HC के बाद CM आतिशी का एक्शन; जांच के दिए निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में नत्थू कॉलोनी आरओबी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। काम पूरा होने के 2-3 महीने के भीतर ही पुल में दरारें आ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अधिकारियों और ठेकेदारों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

**नई दिल्ली।** भाजपा द्वारा नंद नगरी के पास बने नत्थू कॉलोनी आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए कहा है। इसके बाद सीएम आतिशी ने भी सोमवार को इसकी जांच करने का निर्देश दिया है।

सोमवार को मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि यह तथ्य चौंकाने वाला है कि 70 वर्षों से अधिक समय तक बेहतर स्थिति में रहने वाले फ्लाईओवर में काम पूरा होने के मात्र 2-3 महीनों के भीतर दरारें आनी शुरू हो गईं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि परियोजना के क्रियान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार था।

**क्या-क्या होगी जांच**

उन्होंने इस मामले में सख्त नाराजगी जताते हुए मुख्यसचिव को निर्देश दिया है कि इसकी निविदा तैयार करने, कार्य अनुबंध प्रदान करने और 2011-15 में कार्य के निष्पादन की निगरानी करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच करें। परियोजना के पूरा होने के बाद गुणवत्ता नियंत्रण कार्य करने वाली तीसरी पार्टी एजेंसी के खिलाफ जांच करें।

**अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई**

इसके अलावा परियोजना के क्रियान्वयन एवं रखरखाव में घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आतिशी ने लिखे पत्र में कहा है कि इस परियोजना के पूरा होने के 10 वर्षों के भीतर नंद नगरी रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज में आई बड़ी दरारों के बारे में स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

**अधिकारियों की घोर लापरवाही उजागर**

रिपोर्ट में डीटीटीडीसी (DTTDC) और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों (PWD Officials) की ओर से घोर लापरवाही को उजागर किया गया है, जिन्होंने इस दोषपूर्ण परियोजना को अंजाम दिया है, जिससे न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि सैकड़ों लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई है।

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया किया है कि यह 100 करोड़ की लागत वाली परियोजना 10 साल तक भी सार्वजनिक उपयोग के लायक नहीं रह सकी। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सतर्कता कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि इन दोनों पुलों का निर्माण 2011-15 के दौरान किया गया था। शुरुआती निर्माण के दौरान ही नंद नगरी को दुर्गापुरी से जोड़ने वाले कैरिजवे में एक महत्वपूर्ण पैनल में महत्वपूर्ण संरचनात्मक संकट पैदा हो गया था।

**भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने को कहा**

उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 2019 में, इस मामले की जांच के लिए नियुक्त एक कंसल्टेंसी फर्म ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को तत्काल रोकने और डेक स्लैब को पूरी तरह से बदलने की सिफारिश की थी।

सलाहकार की रिपोर्ट बहुत ही तीखी थी क्योंकि इसमें ठेकेदार द्वारा दोषपूर्ण निर्माण के कारण केवल नियमित रखरखाव कार्य की बजाय व्यापक संरचनात्मक मरम्मत की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा है कि यदि रिपोर्ट में बताई गई इतनी बड़ी विसंगतियां थीं तो ठेकेदार और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।ढबता दें कि यह वही फ्लाईओवर है, जिसे लेकर इलाके के भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट ने इस कार्य में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने के लिए कहा है।

## आप सरकार का वकीलों को तोहफा- 3220 नए वकीलों को मिलेगा 10 लाख का टर्म और 5 लाख रुपये का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** "आप" सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 3220 नए वकीलों को 5 लाख रुपये के फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस व 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस देने का फैसला किया है। इस निर्णय को सीएम आतिशी से मंजूरी मिल गई है।

बता दे कि, दिल्ली सरकार अपने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत वर्तमान में 27,000 से ज़्यादा वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है। और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 31,000 हो जाएगी।

इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि, ₹आपक्र सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि, भारत के वकीलों का प्रोफेशन सबने महत्वपूर्ण, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाते है।

चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। उन्होंने साझा किया कि, चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अबतक लगभग 27,000 से ज़्यादा वकील एनरोल हुए और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 31,000 हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि, 2019 में दिल्ली सरकार ने वकीलों की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की, और सालाना इसमें 50 करोड़ रुपये का फण्ड देती है।इसके तहत एनरोल सभी वकीलों को 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। और जब इस स्कीम की शुरुआत हुई उसके तुरंत बाद कोरोना के दौरान ये स्कीम हमारे वकील साथियों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। और हजारों वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि एक सरकार के रूप में हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारी निभाते आये है और आते रहेंगे। हम हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे।

बता दे कि, इस स्कीम के तहत एनरोल वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दिया जाता है। साथ ही ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत वकीलों उनके जीवनसाथी और 25 वर्ष तक के दो आश्रित बच्चों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है।

***योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता***

वकील बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए और दिल्ली के मतदाता होने चाहिए।

## नारायणा मर्डर के पीड़ित परिवार से मिलकर बोले केजरीवाल, "दिल्ली में है जंगलराज"

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को नारायणा पहुंचे और मर्डर पीड़ित परिवार से मिलकर उनका दुख साझा किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भयावह जंगलराज चल रहा है। नारायणा में कुछ महीने पहले ही अपराधियों ने छोटे भाई की हत्या की थी। जिसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और अब उन्हीं अपराधियों ने बड़े भाई की भी हत्या कर दी। आज पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल है, लेकिन अमित शाह और उनकी दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहे। भाजपा की वजह से दिल्ली में जंगलराज है और गुंडे व अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर गृहमंत्री अमित शाह से विनती की कि दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए।

उन्होंने बताया कि यहां पर शनिवार शाम को एक युवा की हत्या कर दी गई। बहुत दुख की बात यह है कि उसी युवा के छोटे भाई का छह महीने पहले मर्डर हुआ था। 22 मई को उनके छोटे भाई का मर्डर किया गया था। जब छोटे भाई का मर्डर किया गया तो इनके परिवार ने पुलिस को लिखकर दिया था कि इन लोगों से पूरे परिवार को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए और हमें इन लोगों से बचाया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और शनिवार को बड़े भाई का भी मर्डर हो गया। यह बेहद दुख की बात है कि यह चल क्या रहा है। यहां पर जब मैं अभी इनसे मिलने के लिए गया, वहां पर कई सारे लोकल लोग मौजूद है। उन्होंने बताया कि पूरा नारायणा एरिया जानता है कि ये 5-7 लड़के हैं, जिन्होंने पूरे इलाके में गदर मचा रखा है। सभी को परेशान करते हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक मर्डर के बाद जब पुलिस को लिखकर दिया गया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, पुलिस ने क्यों नहीं की? जिस शख्स का मर्डर हुआ, रविवार को उसके परिवार के लोग दुख, दहशत की वजह से प्रदर्शन करने के लिए शव को लेकर बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उनके परिवार के लोगों पर डंडे बरसाए। यह किस किस्म का प्रशासन है? यह किस किस्म की कानून-व्यवस्था है? पूरी दिल्ली के अंदर रविवार को अलग-अलग तीन मर्डर हुए हैं और एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। दिल्ली के लोग पूरी तरह से असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा ने पूरी दिल्ली को गुंडों, गैंगस्टर्स और बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाएं?

उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर भाजपा वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था। जब चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई है, जंगल राज है। कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है। जब पता था कि जिन लोगों ने छोटे भाई मर्डर किया है, वो उनके परिवार के और लोगों का भी मर्डर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? छह महीने बाद दूसरे भाई का उसी परिवार के अंदर मर्डर हो जाता है, यह सुनकर भी बहुत दुख होता है। अमित शाह और भाजपा वाले कृपया दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है और दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गैंगस्टर्स के केस में भी, जब मैं बिजनेसमैन से मिलने गया तो उन लोगों ने बताया कि दो-तीन लड़के बाइक पर आते हैं और दुकान पर गोली चलाते हैं, उन्हें तो अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उनको जिन्होंने भेजा, जो फिरौती की मांग कर रहे हैं, जो असली गैंगस्टर्स हैं, वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। गैंगस्टर्स के नाम सबको पता हैं कि कौन गैंगस्टर्स हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

## ईपीएफओ की माफी योजना 2024 को मंजूरी: छोटे उद्योगों के लिए बड़ी राहत

इशिका मुख्य रिपोर्टर रांची झारखंड न्यूज
परिवहन विशेष

**नई दिल्ली।** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए राहत भरी खबर दी है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 'माफी योजना 2024' को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, नियोक्ता अपने पुराने गैर-अनुपालन या कम अनुपालन को बिना किसी दंड के सुधार सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य न केवल औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, बल्कि छोटे उद्योगों को ईपीएफओ में आसानी से पंजीकरण करने का भी प्रोत्साहन देना है।

***श्रम मंत्रालय करेगा स्कीम लागू***

श्रम और रोजगार मंत्रालय अब इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगा। योजना को वर्ष के अंत तक *'एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम'* के साथ लागू किया जाएगा।

श्रम मंत्रालय ने कहा, "यह माफी योजना उन छोटे उद्योगों को आत्मविश्वास देगी, जो ईपीएफओ में पंजीकरण को लेकर चिंतित थे। उन्हें अब गैर-अनुपालन की वजह से वित्तीय दंड का डर नहीं होगा।"

***एमएसएमई सेक्टर को होगा बड़ा फायदा***

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना एमएसएमई और अन्य छोटे उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। एमएसएमई इकाइयों के कई छोटे नियोक्ता, जो अब तक ईपीएफओ में एक पंजीकरण से बचते थे, अब इस योजना का लाभ उठाकर अपनी इकाइयों को औपचारिक रोजगार का हिस्सा बना सकते हैं।

***बोर्ड ने लिए कई और अहम फैसले***

ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, ने अपनी 236वीं बैठक में माफी योजना के अलावा कई और बड़े फैसले लिए। इनमें शामिल हैं:

1. केंद्रित ईपीएफ अंशदान संग्रह के लिए बैंक पैनल का सरलीकरणः इससे नियोक्ताओं के लिए काम करना आसान होगा।

2. सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज भुगतानः अब ब्याज केवल पिछले महीने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्लेम की तारीख तक दिया जाएगा।

3. क्लेम निपटान प्रक्रिया में सुधारः इससे लंबित मामलों में कमी आएगी और सदस्यों को समय पर सेवाएं मिलेंगी।

***क्या है योजना की खासियत?***

माफी योजना 2024 का लक्ष्य नियोक्ताओं को पुराने अनुपालन को सुधारने का मौका देना है। इससे ईपीएफओ में नए पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और औपचारिक रोजगार सृजन का रास्ता खुलेगा। यह कदम एमएसएमई सेक्टर के साथ-साथ पूरे रोजगार बाजार को संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

***सदस्यों को मिलेगा सीधा फायदा***

नए फैसले के तहत, ईपीएफओ अब सदस्यों को उनके क्लेम की तारीख तक ब्याज का भुगतान करेगा। इससे सदस्यों को आर्थिक लाभ होगा और शिकायतों में भी कमी आएगी।

***सभी को है फैसले का इंतजार***

ईपीएफओ के इन फैसलों से लाखों छोटे उद्योग और उनके कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। अब सभी को श्रम मंत्रालय से इस योजना को जल्द लागू करने की उम्मीद है।

***हमारी सलाहः***

नियोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर ईपीएफओ में पंजीकरण करें और औपचारिक रोजगार व्यवस्था का हिस्सा बनें। यह न केवल नियोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।

# अपील - हमारी सेवा में लगे वेटर या किसी भी पेशे में काम करने वाले व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

अगर हम उनके साथ अच्छे और आदर्श तरीके से पेश आएं, तो समाज में सच्चा प्रेम और समझ बढ़ेगा : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

वेटर, दिहाड़ी मजदूर, या किसी भी पेशे में काम करने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाना हमारी जिम्मेदारी : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

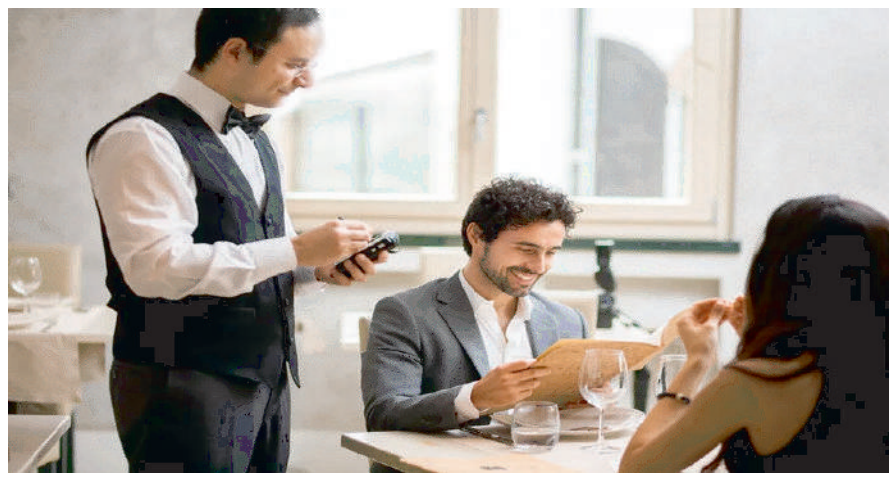

**आगरा,संजय साग़र सिंह।** उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री एवं सामाजिक चिंतक वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने कहा, ₹समाज में अक्सर हमें कामकाजी लोगों को उनके पेशे के आधार पर नज़रअंदाज़ किया जाता है या उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता। वेटर, दिहाड़ी मजदूर, या किसी भी पेशे में काम करने वाले व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। ये लोग हमारे आराम और सुख के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और उनका हर काम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने आगे कहा, ₹जब भी हम शादी-बरात या किसी भी प्रोग्राम में जाए तो वेटर को इज्जत के साथ बुलाए ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। वेटर या किसी भी पेशेवर के लिए सम्मान और आदर दिखाना बहुत जरूरी है। यह न केवल उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे अपने चरित्र और संस्कृति को भी दर्शाता है। जब भी हम शादी-बरात या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर वेटर अक्सर हमारी सेवा में खड़े रहते हैं, और हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा, जब हम वेटर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो इससे हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-संतुष्टि में भी सुधार होता है।

अंत में, श्री खान ने कहा, "कोई भी हो किसी भी व्यवसाय काम से जुड़े लोग मजदूर हो अगर हम आपको उनसे सम्मान प्यार से बात करे। जब हम किसी को इज्जत और प्यार के साथ पेश आते हैं, तो न केवल उनकी मेहनत की कद्र होती है, बल्कि हमारे दिल में भी एक संतोष और शांति महसूस होती है। यह एक सकारात्मक संदेश फैलाता है कि हम समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, चाहे वे किसी भी पेशे में हों। इस तरह का व्यवहार न केवल दूसरों को खुश करता है, बल्कि हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हर किसी का काम मायने रखता है, और अगर हम हर व्यक्ति के साथ अच्छे और आदर्श तरीके से पेश आएं, तो समाज में सच्चा प्रेम और समझ बढ़ेगा।

# मथुरा जनपद में सिविल डिफेंस ने चलाया स्वच्छता अभियान

परिवहन विशेष न्यूज

**मथुरा:** दिनांक 2 दिसंबर 2024 को नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह जी के नेतृत्व में वार्डन पोस्ट संख्या एक में स्थित नागरिक सुरक्षा पार्क और गोकुल के घाटों पर लाईफ जैकिट पहन कर डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी एवं पोस्ट वार्डन अशोक यादव की टीम के द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई अभियान चलाया गया सफाई अभियान में नागरिक सुरक्षा मथुरा के सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह, डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी, पोस्ट वार्डन अशोक यादव, अरविंद चौधरी, सैक्टर वार्डन राम सैनी, गोविन्द, रिंकी, शुभम्कुमार, राकेश, रिंकी, जवर सिंह एवं आदि वार्डन स्वयंसेवक मौजूद रहे।

# नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर प्रतिभा की खोज जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं समान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

**मथुरा:** नागरिक सुरक्षा विभाग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 01 दिसम्बर 2024 को दिन रविवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्डन पोस्ट संख्या एक के पोस्ट वार्डन अशोक यादव के द्वारा प्रतिभा की खोज जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं समान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2024 का आयोजन औरंगाबाद स्थित जी डी पब्लिक स्कूल पर 450 बच्चो ने प्रतिभाग किया जिसमें नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह , चीफ वार्डन राजीव अग्रवाल, डिप्टी चीफ वार्डन कल्याण दास अग्रवाल, डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी, सीनियर स्टॉफ ऑफिसर टू चीफ वार्डन दीपक चतुर्वेदी बैंकर, घटना नियंत्रक अधिकारी अजय कांत गर्ग, वर्षा रामनाड़ी के द्वारा परीक्षा सेन्टर पर जाकर बच्चो का निरक्षण किया गया जिसमें सभी छात्र छात्राएं में पेपर को लेकर जोश दिखा साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के पोस्ट वार्डन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा मित्र अशोक यादव के द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के कॉम्पटीशन हम 2019 से लगातार कराते आ रहे हैं जिसमें हर वर्ष मथुरा , गोवर्धन, बृंदावन तक के विद्यार्थी भाग लेते हैं जिसमें नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से 20 सवाल पूछे जाते है और बही समान्य ज्ञान से 40 सवाल और 20 सवाल गणित से 10 सवाल इंग्लिश से 10 सवाल हिन्दी से इसी प्रकार 100 सवालों का एक पेपर होता है इसके बाद मेरिट के आधार पर इनको जिला प्रशासन एवं नागरिक सुरक्षा मथुरा के द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग के 6 दिसंबर स्थापना दिवस के मौके पर सिविल लाईन कलेक्ट्रेट स्थित नागरिक सुरक्षा मथुरा कार्यालय पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा। नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के पोस्ट वार्डन अशोक यादव के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य गिर्राज सिंह, डिप्टी पोस्ट वार्डन विकास सोनी सैक्टर वार्डन राम सैनी, शुभम्-कुमार, राजेश कुमार, देवेन्द्र कुमार, सुनैना, फायर फाइटर रोहित कुशवाह , धर्मेन्द्र तोमर, हेमंत, पंकज गर्ग, सोहन लाल, आदि के द्वारा परीक्षा को सफ़ल बनाने में अहम भूमिका निभाई गई।

# अमेरिकी मूल्यों से लबरेज़ परोकार ,बेहतरीन टीम के साथ व्हाइट हाउस में आ रहे हैं ट्रंप... ! प्रशासन में भारतवंशियों का दबदबा !

ट्रंप के आते ही बांग्लादेश मामले पर सख़्ती ब्रिक्स करेंसी पर लगाम व भारत से अटूट दोस्ती प्रयागढ़य होने की संभावना– एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर सारी दुनियाँ की नज़रे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क़े व्हाइट हाउस जाकर पद संभालने पर लगी हुई है, क्योंकि उनके चुने जाने भर से ही इज़राइल हमास का 60 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में डॉलर के स्थान पर ब्रिक्स करेंसी का विचार, बांग्लादेश चीनपाकिस्तान पर नकेल कसने की बातों सहित अनेक निर्णयों पर एक्शन रिएक्शन की संभावना का बाजार गर्म हो गया है तो दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन के लिए, की जा रही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे, मूल भारतवंशियों की झोली में आई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्रंप की बेहतरीन टीम में अभी तक शामिल साथी भारत को एक सहयोगी के रूप में देखते हैं, इसलिए बांग्लादेश के इस्कॉन पीठाधीश की गिरफ्तारी, जमानत रद्द कर जेल भेजने तथा अन्यों की गिरफ्तारी व भारत बांग्लादेश संबंधों की खराबी के एक्शन पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है तो वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स सम्मेलन में डॉलर के स्थान पर ब्रिक्स करेंसी लाने के विचार पर भी रिएक्शन आ गया है, शनिवार दिनांक 30 नवंबर 2024 को देर शाम ट्रंप का बयान आया कि भारत सहित 9 देशों को खुली चेतावनी देकर कहा ऐसा हुआ तो 100 पेर्सेंट टैरिफ लगाकर अमेरिकी बाजार उन देशों के लिए बंद कर देंगे, सहित अन्य मुद्दों पर पूरी दुनियाँ की नज़रें लगी हुई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से, इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, अमेरिकी मूल्यों से लबरेज परोकार बेहतरीन टीम के साथ पद संभालने व्हाइट हाउस में आ रहे हैं ट्रंप...ट्रंप प्रशासन में भारतवंशियों का दबदबा दिखने की संभावना ?

साथियों बात अगर हम ट्रंप प्रशासन क़े व्हाइट हाउस आने व भारतवंशियों के ट्रंप प्रशासन में दबदबा दिखने की संभावना की करें तो, अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। वे शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के उच्च पदों से लेकर देश की राजनीति में भी अहम पदों तक पहुंच रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आगामी प्रशासन के लिए अब तक कई भारतवंशियों को नामित कर चुके हैं। जबकि ट्रंप के पूर्व आध्यात्मिक सलाहकार जानी मूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय रिपब्लिकन नेता के दूसरे कार्यकाल के केंद्र में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर पद के लिए नामित किया। पटेल ट्रंप के प्रशासन में कानून और सुरक्षा को मजबूत करेंगे। ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए चुना है। साथ ही, तुलसी गबार्ड और जय भट्टाचार्य को भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली हैं। उषा वेंस ट्रंप प्रशासन की नई सेकंड लेडी बनेंगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को संघीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर पद के लिए अपने निकट सहयोगी एवं विश्वासपात्र काश पटेल को नामित किया। यह सेलेक्शन ट्रंप के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही ट्रंप ने अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रतिशोध की इच्छा जताई है। ऐसे में इस पद के लिए पटेल का चयन मायने रखता है। काश पटेल की नियुक्ति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही। पटेल अमेरिका में कानून व्यवस्था और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। 44 वर्षीय पटेल 2017 में तत्कालीन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम कुछ हफ्तों में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम कर चुके हैं। पेशे से वकील पटेल का संबंध गुजरात में वडोदरा से रहा है। पटेल भारत में अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर दिए बयान की वजह से भी चर्चा में रहे थे। निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए चुना है। बिजनेसमैन रामास्वामी का काम सरकार को सलाह देना होगा। भारतवंशी रामास्वामी करोड़पति शख्स हैं और एक दवा कंपनी के फाउंडर भी हैं। वें राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने ट्रंप का समर्थन करने का फैसला किया था। उनके माता-पिता केरल से अमेरिका चले गए थेसिनसिनाटी, ओहियो में जन्मे और पले-बढ़े, भारतीय मूल के बिजनेसमैन राष्ट्रीय स्तर के टेनिस खिलाड़ी थे। डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व सदस्य तुलसी गबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (डीएनआई) के रूप में सेवाएं देंगी। गबार्ड चार बार सांसद रह चुकी हैं। वह 2020 में वह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थीं। गबार्ड के पास पश्चिम एशिया और अफ्रीका के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में तीन बार तैनाती का अनुभव है। वह हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थीं। ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के टॉप हेल्थ रिसर्च एवं वित्त पोषण संस्थानों में से एक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) के निदेशक के रूप में चुना है। इसके साथ ही भट्टाचार्य, ट्रंप द्वारा शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। डॉ. भट्टाचार्य रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर के साथ मिलकर राष्ट्र के मेडिकल रिसर्च की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे भारतीय अमेरिकी वकील उषा चिलुकुरी वेंस उस समय चर्चा में आईं, जब उनके पति जे डी वेंस को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया। ट्रंप-वेंस की जीत के साथ, 38 साल की उषा अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली हैं। इस भूमिका में उषा पहली भारतीय-अमेरिकी होंगी। उषा, ओहियो के सीनेटर जे डी वेंस (39) के साथ खड़ी थीं, जब ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद समर्थकों को संबोधित किया

साथियों बात अगर हम भारत बांग्लादेश तनाव व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार में अमेरिकी प्रभाव की करें तो, हाल के दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की ख़बरों और सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के राजनयिक रिश्तों में कड़वाहट साफ दिख रही है। इस मामले को लेकर बांग्लादेश और भारत, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ टिप्पणी कर चुके हैं। दोनों जगह एक दूसरे के ख़िलाफ़ अभियान और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। ताज़ा घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ प्रमुख लोगों और विश्लेषकों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या सरकार अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं को आंतरिक और कूटनीतिक तौर पर ठीक तरह से संभाल पाने में पूर्ण सक्षम है ? ऐसे में अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि, अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया है, यह समय बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व पर खतरे की तरह है। लेकिन ट्रंप अब आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में धार्मिक स्वतंत्रता मानवाधिकारों में शीर्ष प्राथमिकता थी। अमेरिका और भारत के बीच ऐसा सहयोग देखने को मिलेगा, जो अभी तककभी भी नहीं देखने को मिला था।

साथियों बात अगर हम ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स करेंसी लाने पर विचार के रिएक्शन की करें तो, भारत समेत 9 देशों को ट्रंप की खुली चेतावनी, ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने हैंडल पर लिखा, डॉलर से दूर होने की ब्रिक्स देशों की कोशिश में हम मूकदर्शक बने रहें, यह दौर अब ख़त्म हो गया है, हमें इन देशों से प्रतिबद्धता की ज़रूरत है कि वे न तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही ताक़तवर अमेरिकी डॉलर की जगह लेने के लिए किसी दूसरी मुद्रा का समर्थन करेंगे, वरना उन्हें 100 प्रतिशत टैरिफ़ का सामना करना पड़ेगा उन्होंने लिखा अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपने उत्पाद बेचने को विदा कहना होगा, वे किसी दूसरी जगह तलाश सकते हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की जगह ले पाएगा और ऐसा करने वाले किसी भी देश को अमेरिका को गुडबॉय कह देना चाहिए। बीते अक्तूबर में रूस के शहर कज़ान में ब्रिक्स की बैठक हुई थी और उस दौरान भी इस ब्लॉक की ओर से अपनी मुद्रा बनाने से जुड़े कयास लगाए जा रहे थे।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अमेरिकी मूल्यों से लबरेज़ परोकार बेहतरीन टीम के साथ व्हाइट हाउस में आ रहे हैं ट्रंप.... ! प्रशासन में भारतवंशियों का दबदबा ! ट्रंप की बेहतरीन टीम में शामिल साथी भारत को एक सहयोगी के रूप में देखते हैं ? ट्रंप के आते ही बांग्लादेश मामले पर सख़्ती, ब्रिक्स करेंसी पर लगाम व भारत से अटूट दोस्ती प्रयागढ़य होने की संभावना।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

# मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, के बाद अब ऑडी भी बढ़ाएगी कीमतें, जान लें किस तारीख से कितनी महंगी हो जाएंगी कारें

परिवहन विशेष न्यूज

बाजार में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कारों और एसयूवी को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। समय समय पर इनकी कीमतों में भी बदलाव होता रहता है। Mercedes और BMW जैसे निर्माताओं के बाद अब Audi की ओर से भी कीमतों को बढ़ाने की घोषणा की गई है। कंपनी कब से और कितनी कीमत बढ़ाने (Audi price hike 2024) की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माता Audi की ओर से भी भारत में कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से अपनी कारों की कीमतों को बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। Audi की ओर से कब से कीमतों को बढ़ाया जाएगा। कारों को कितना महंगा (Audi car price increase) किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**कीमत में होगी बढ़ोतरी**

ऑडी की ओर से भारतीय बाजार में कीमतों को बढ़ाने (Luxury car price hike) की तैयारी कर ली गई है। अगर आप भी कंपनी की किसी गाड़ी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ इसी महीने गाड़ी को खरीदना बेहतर हो सकता है।

**कब से बढ़ेंगी कीमतें**

ऑडी इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए साल में एक जनवरी 2025 से कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक ऑडी की कीमतों में तीन फीसदी तक (Audi new prices) की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन सभी कारों पर एक समान कीमतों को नहीं बढ़ाया जाएगा।

**इस कारण से बढ़ेगी कीमत**

ऑडी की ओर से बताया गया है कि इनपुट और ट्रांसपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस कारण कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है।

**अधिकारियों ने कही यह बात**

ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लो ने कहा कि हम बढ़ती इनपुट लागत के कारण 1 जनवरी 2025 से 3 फीसदी तक कीमतों को बढ़ाने जा रहे हैं। ऑडी इंडिया और हमारे डीलर भागीदारों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए यह सुधार आवश्यक है। हम अपने मूल्यवान ग्राहकों पर मूल्य बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

**कैसा है पोर्टफोलियो**

ऑडी की ओर से भारत में कई कारों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली कारों में Audi A4, Audi A6, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8, Audi S5 Sportback, Audi RS5 Sportback, Audi RS Q8, Audi Q8 50 e-tron, Audi Q8 55 e-tron, Audi Q8 Sportback 50 e-tron, Audi Q8 Sportback 55 e-tron, Audi e-tron GT और Audi RS e-tron GT शामिल हैं।

**इन लग्जरी कार निर्माताओं ने भी की घोषणा**

ऑडी की ओर से कीमतों को बढ़ाने की घोषणा से पहले दो और जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माताओं की ओर से कीमतों को बढ़ाने का एलान किया जा चुका है। इनमें Mercedes Benz और BMW भी शामिल हैं।

# काइनेटिक कम्युनिकेशन लिमिटेड ने पुणे में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर प्लांट और L3 किट किया लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन पावरट्रेन समाधानों में अग्रणी काइनेटिक कम्युनिकेशन लिमिटेड ने भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वृद्धि का समर्थन करने की दिशा में दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कंपनी ने पुणे के चिंचवाड़ में एक नए मोटर प्लांट का उद्घाटन किया और अपने ई-पॉवरशिफ्ट सेल्स मीट के दौरान इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए L3 किट लॉन्च की।

नया उद्घाटन किया गया मोटर प्लांट 3,000 वर्ग मीटर में फैला है और दो-, तीन- और चार-पहिया वाहनों के लिए उच्च दक्षता वाले BLDC और PMSM का उत्पादन करने के लिए उन्नत तकनीकों से लैस है। इस सुविधा में स्टेटर और रोटर के लिए समर्पित असेंबली लाइनें, एक उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला, इन-हाउस वाइंडिंग क्षमताएं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से ऊर्जा-कुशल अभ्यास शामिल हैं। प्लांट को स्थिरता को बढ़ावा देते हुए ईवी बाजार की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

काइनेटिक कम्युनिकेशन लिमिटेड के संस्थापक अरुण फिरोदिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सुविधा परिवहन के भविष्य को आकार देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्नत विनिर्माण तकनीकों और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं के संयोजन का उद्देश्य वाहन के प्रदर्शन को बेहतर बनाना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र के विकास का समर्थन करना है। मोटर प्लांट के अलावा, काइनेटिक कम्युनिकेशन ने ई-पॉवरशिफ्ट सेल्स मीट में L3 किट भी लॉन्च की। L3 किट विशेष रूप से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बाज़ार में प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करना है। यह किट बढ़ती बाज़ार मांग के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन समाधानों का समर्थन करती है। ई-पॉवरशिफ्ट सेल्स मीट में दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों से काइनेटिक की बिक्री टीम और डीलर भागीदार एक साथ आए। नेतृत्व टीम ने इस कार्यक्रम का उपयोग कंपनी के रणनीतिक रोडमैप को साझा करने और नवाचार, स्थिरता और मेक इन इंडिया पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए किया। काइनेटिक ग्रुप के वाइस चेयरमैन अजिंक्य फिरोदिया ने कहा कि एल3 किट का लॉन्च इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संधारणीय समाधानों को आगे बढ़ाने और ईवी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर कंपनी के फोकस के अनुरूप है।

नए मोटर प्लांट का उद्घाटन और एल3 किट का लॉन्च भारत के संधारणीय गतिशीलता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में काइनेटिक कम्युनिकेशन लिमिटेड की भूमिका को पुख्ता करता है। आधुनिक विनिर्माण क्षमताओं में निवेश करके और अभिनव ईवी समाधान पेश करके, कंपनी अधिक कुशल और संधारणीय शहरी गतिशीलता की ओर संक्रमण का समर्थन कर रही है।

# द रॉक्स और स्कॉर्पियो के दम पर महिंद्रा की बढ़ी बिक्री, नवंबर 2024 में कैसा रहा प्रदर्शन

भारत की प्रमुख एसयूवी निर्माता Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से November 2024 के बिक्री के आंकड़ों को जारी किया गया है। बीते महीने के दौरान बिक्री के मामले में महिंद्रा का कैसा प्रदर्शन रहा है। कितनी यूनिट्स की बिक्री घरेलू बाजार में की है और कितनी यूनिट्स का एक्स सपोर्ट किया है। आइए जानते हैं।

**नई दिल्ली।** देश की प्रमुख एसयूवी निर्माता Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से नवंबर 2024 में हुई बिक्री की रिपोर्ट को जारी किया गया है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक बीते महीने के दौरान कुल कितनी यूनिट्स की बिक्री हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। November 2024 के दौरान कितनी यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

**कितनी हुई बिक्री:** महिंद्रा की ओर से नवंबर 2024 के दौरान हुई बिक्री की रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने बीते महीने के दौरान कुल 46222 यूनिट्स की बिक्री देशभर में की है। वहीं 1072 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर कंपनी ने November 2024 के दौरान 47294 यूनिट्स की बिक्री की है।

**पिछले साल कैसा था प्रदर्शन :** ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो कंपनी ने 16 फीसदी की बढ़त हासिल की है। November 2023 के दौरान घरेलू बाजार में महिंद्रा ने 39981 यूनिट्स की बिक्री की थी।

**कंपनी के अधिकारियों ने कही यह बात :** महिंद्रा ऑटो के ऑटोमोटिव डिविजन प्रमुख विजय नाकरा ने कहा कि हमने नवंबर में 16 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 46222 SUV बेचीं और कुल 79083 वाहन बेचे। इस महीने हमारी सबसे प्रतीक्षित इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV - BE6e और XEV9e लॉन्च हुई हैं। जिनको INGLO पर बनाया गया है। ये वाहन महिंद्रा के अनलिमिटेड इंडियाज के विज़न को मूर्त रूप देते हैं - एक ऐसा युग जहाँ भारतीय नवाचार और डिज़ाइन न केवल वैश्विक मानदंडों को चुनौती देते हैं बल्कि नए मानदंड भी स्थापित करते हैं। इन इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV के लिए बाज़ार में जनवरी 2025 के उत्तरार्ध में चरणबद्ध तरीके से जाना शुरू होगा। डिलीवरी फरवरी के अंत या मार्च 2025 की शुरुआत में शुरू होगी।

**किन एसयूवी की होती है सबसे ज्यादा मांग :** भारतीय बाजार में कंपनी की ओर से कई बेहतरीन एसयूवी को ऑफर किया जाता है। लेकिन बाजार में सबसे ज्यादा मांग Mahindra Scorpio और Scorpio N, Mahindra XUV 700 और Mahindra Thar Roxx की रहती है। इनके अलावा भी XUV 3XO को भी काफी पसंद किया जाता है।

**कैसा है पोर्टफोलियो:** महिंद्रा के पोर्टफोलियो में Mahindra Bolero Classic, Mahindra Bolero Neo, Mahindra XUV 3XO, Mahindra Thar, Mahindra Thar Roxx, Mahindra Scorpio Classic, Mahindra Scorpio N, Mahindra XUV 700 जैसी दमदार एसयूवी आईसीई सेगमेंट में आती हैं। वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी की ओर से Mahindra XUV 400 EV को ऑफर किया जाता है। इनके अलावा हाल में ही कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में XEV 9e और Mahindra BE 6e को लॉन्च किया गया है।

# राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर ईवी निर्माताओं ने पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश

परिवहन विशेष न्यूज

2024 के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम है "स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी: संधारणीय जीवन की ओर एक कदम"। यह हमारी हवा, पानी और मिट्टी को प्रभावित करने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल में घातक गैस एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हजारों लोग मारे गए थे। भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे घातक औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक है। इस दिवस का आयोजन नागरिको को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करने एवं इसके प्रबंधन, नियंत्रण एवं समुचित निस्तारण के लिए प्रभावी उपाय करने के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है।

यह दिवस किसी भी औद्योगिक आपदा को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। भारत में हर साल लगभग 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, जबकि घर के अंदर के वायु प्रदूषण से 40 लाख लोग मारे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10 में से नौ लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है। प्रदूषक बहुत छोटे होते हैं जो फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने के लिए श्लेष्मा झिल्ली और अन्य सुरक्षात्मक बाधाओं से गुजर सकते हैं।

इस अवसर पर ईवीएक्सपो के संयोजक राजीव अरोड़ा ने कहा कि "माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या" धरती हमारी मां है और मां ने हम सबको स्वच्छ जल, वायु और पर्यावरण दिया है। हम सबका भी कर्तव्य है कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचायें। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए Reduce, Reuse और Recycle के मंत्र को आत्मसात करें।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रबंध निदेशक जितेंदर ठुकराल ने कहा कि आइए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर हम शपथ लें कि पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भागीदार बनेंगे। स्वंय प्रदूषण फैलाने से बचे तथा समाज को भी जागरुक करेंगे।

प्लगएन राइड के एमडी ज़फ़र इकबाल ने लोगों से आह्वान किया हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पर्यावरण का होना बेहद जरूरी है, तो चलिए इस राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को बचाने में सहयोग करने का संकल्प लें।

ट्रम्प ईवी पार्ट्स के राजीव चुग ने अपने संदेश मे कहा कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर हवा, पानी, मिट्टी, पर्यावरण और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को ना फैलाने का संकल्प करें एवं प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता फैलाएं।

1984 में 2 और 3 दिसंबर को भोपाल गैस आपदा में मरने वालों को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन दिसंबर में लगभग 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय इकाई के स्वामित्व वाले एक रासायनिक संयंत्र से निकल गई। कुछ ही मिनटों में जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली थी।

# भारत का सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक Thukral EC-3 Closed Cargo

परिवहन विशेष न्यूज

ठकराल इलेक्ट्रिक का सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय EC-3 Closed Cargo है, जिसे विशेष रूप से छोटे व मध्यम व्यवसायों और लास्ट-माइल डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह EC-3 Closed Cargo अपनी बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस, शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ प्रदूषण रहित माल डिलीवरी के लिए जाना जाता है। EC-3 Closed Cargo को Thukral Electric Bikes ने कई तरह के व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है, चाहे वह सब्जियों और फलों की ढुलाई हो, किराना सामान की डिलीवरी हो या फिर छोटे, मध्यम व बड़े पैकेट, जैसे धूप या बारिश से खराब होने वाली वस्तुओं को लास्ट-माइल डिलीवरी तक पहुंचाने के लिए EC-3 Closed Cargo एक बेहतरीन विकल्प है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के डिजाइन की बात की जाए तो इस EC-3 Closed Cargo का डिज़ाइन कॉम्पैक्ट और फंक्शनल रखा गया है, जिसकी वजह से यह शहर की तंग गलियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में आसानी से चलाया जा सकता है। इसका मजबूत चेसिस और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से खराब सड़को पर भी EC-3 Closed Cargo आसानी से चलाया जा सकता हैं।

EC-3 Closed Cargo का केबिन भी ड्राइवर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त स्पेस दिया गया है, जिसमें आरामदायक सीटें और आसान कंट्रोल्स लगाए गए है। EC-3 Closed Cargo को भारी लोड के साथ खराब सड़को पर चलाने के लिए इसका सस्पेंशन सेटअप स्मूथ राइड देने का काम करता है।

EC-3 Closed Cargo की माइलेज 150+ किलोमीटर और पेलोड क्षमता लगभग 700 से 800 किलोग्राम है, जो इसे विभिन्न प्रकार के माल ढुलाई के लिए उपयुक्त बनाती है। इसका मजबूत चेसिस और टिकाऊ बॉडी डिज़ाइन इसे भारी भार उठाने और ढोने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यह सब्जी-फल, किराना और अन्य कमर्शियल सामान की डिलीवरी के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।

Thukral EC-3 Closed Cargo में कई प्रैक्टिकल फीचर्स लगाए गए हैं जो इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, आरामदायक सीट्स और एक बड़ा फ्रंट विंडशील्ड लगाया गया है, जो ड्राइवर को बेहतर विजिबिलिटी देता है। इसके अलावा EC-3 Closed Cargo का सस्पेंशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया लगाया गया है जो इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी एक स्मूथ राइड देने का काम करता है।

Thukral EC-3 Closed Cargo में सेफ्टी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस EC-3 Closed Cargo का मजबूत चेसिस और बॉडी स्ट्रक्चर दुर्घटना की स्थिति में अधिक सेफ्टी देता है। इसके अलावा Thukral

Electric Bikes ने इसमें बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम लगाए है जो एमरजेंसी की स्थिति में अचानक ब्रेक लगाने पर भी स्टेबिलिटी बनाए रखता है।

# इज़रायली कंपनी ने नॉर्वे में पहली वायरलेस ईवी चार्जिंग सड़क स्थापित की

**यरूशलम।** इजरायल की हाई-टेक कंपनी इलेक्ट्रियन वायरलेस ने नॉर्वे में पहली वायरलेस चार्जिंग रोड स्थापित की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को चलते समय चार्ज करने की सुविधा मिलेगी, कंपनी ने रविवार को तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी।

इलेक्ट्रियन की सड़क चार्जिंग प्रणाली सड़क की सतह के ठीक नीचे स्थित विशेष तांबे की कॉइल का उपयोग करती है। 100 मीटर लंबा नया सड़क खंड ट्रॉनहेम शहर में बनाया गया था और इसकी लगभग एक साल तक जांच की जाएगी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह परीक्षण चीनी दिग्गज कंपनी यूटोंग द्वारा निर्मित तीन इलेक्ट्रिक बसों और चीनी बस निर्माता कंपनी हाइगर द्वारा निर्मित चौथी बस के साथ किया जाएगा।

पायलट अभियान में बसों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी की क्षमता की जांच की जाएगी, जिससे बसों का दिन भर चार्जिंग स्टॉप के बिना निर्बाध संचालन संभव हो सकेगा और इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

परीक्षणों में चार्जिंग सिस्टम को ट्रॉनहैम की कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में भी परखना शामिल होगा, ताकि इस उत्तरी क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु में इसकी लचीलापन और प्रभावशीलता को साबित किया जा सके।

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 22.4 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर (2.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जिसका वित्तपोषण नॉर्वे सरकार द्वारा किया जाएगा।

# डिजिटल युग में स्त्री सशक्तीकरण

विजय गर्ग

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट तक महिलाओं की पहुंच में सुधार सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सशक्तीकरण के लिए नहीं, बल्कि यह समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। डिजिटल प्रौद्योगिकी महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय स्वतंत्रता के नए अवसर प्रदान कर सकती है, जो समाज में लैंगिक असमानता को कम करने में मदद करती है। हालांकि, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन प्रयासों में महिलाओं की कमजोरियों और सुरक्षा संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जाए। भारत में 'डिजिटल डिवाइड', विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में, एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी है। 'ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन' और 'आक्सफैम ' के 2022 और 2023 के आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच सुधार की आवश्यकता है। मसलन, 2022 में मोबाइल स्वामित्व में लैंगिक अंतर में 11 फीसद की कमी आई है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट उपयोग में महिलाओं का हिस्सा 130 1 फीसद पर स्थिर है, जिससे लैंगिक अंतर 40 फीसद तक बढ़ गया है। इसके अलावा, महिलाओं में मोबाइल इंटरनेट जागरूकता 60 फीसद से भी कम है। यह दर्शाता है कि महिलाओं को डिजिटल दुनिया पूरी तरह से समाहित करने के लिए अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

'महिलाओं के लिए डिजिटल': जुड़ाव की चुनौतियां सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हैं। महिलाओं को साइबर दुर्व्यवहार, आनलाइन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करती हैं। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को बल्कि उनके डिजिटल जुड़ाव को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भारत में इंटरनेट, मोबाइल फोन की पहुंच और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि इन इन सुधारों को लैंगिक समानता की दृष्टि से लागू किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच इंटरनेट उपयोग में गहरा अंतर है, जहां पुरुषों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना महिलाओं की तुलना में दोगुनी है। नतीजतन, महिलाओं के लिए डिजिटल अवसरों तक पहुंच में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे उनके आर्थिक अवसरों में समझौता होता है। । डिजिटल साक्षरता की कमी और मोबाइल इंटरनेट उपयोग की जटिलताएं इस अंतर को और बढ़ा देती हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की की गई 'डिजिटल इंडिया' पहल ने डिजिटल पहुंच को बढ़ाने का महत्वपूर्ण किया है, लेकिन इस पहल में महिला केंद्रित मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। गुरुमूर्ति और चामी ( 2018 ) के अनुसार, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दस्तावेज में कोई स्पष्ट लिंग-विभाजित प्रशिक्षण लक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे महिलाओं को डिजिटल दुनिया में समावेशी रूप से शामिल करने में असमर्थता व्यक्त होती है। इसके अलावा, यह पहल यह पहचानने में भी विफल है कि महिलाओं द्वारा इंटरनेट उपयोग की दर में वृद्धि के लिए डिजिटल साक्षरता और कौशल के अवसरों की आवश्यकता है।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों का समावेशी विकास समाज में सभी वर्गों को आर्थिक मौके, शिक्षा और गतिशीलता संबंधी बाधाओं को पार करने का अवसर प्रदान कर सकता है। डिजिटल तकनीकें नई नौकरियां पैदा कर, डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुगम बना और डिजिटल व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसके अलावा, डिजिटल प्रौद्योगिकी से सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने और नागरिकों की अधिक सहभागिता को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है।

भारत में इंटरनेट उपयोग तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस प्रगति के बावजूद, डिजिटल विभाजन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार भारत में केवल 33 फीसद महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, जबकि 57 फीसद पुरुषों ने इसका उपयोग किया है। स्मार्टफोन के आंकड़े इस असमानता को और स्पष्ट करते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 26 फीसद महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, जबकि 49 फीसद पुरुष स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता और गहरी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण भारत पुरुषों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना महिलाओं की तुलना में ल लगभग दोगुनी है। पूरे भार भारत में ऐसा कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जहां महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में इंटरनेट का अधिक उपयोग किया हो। महिलाओं की डिजिटल कनेक्टिविटी का सीधा असर उनके वित्तीय सशक्तीकरण पर भी पड़ता है। 'डिजिटल बैंकिंग' और 'मोबाइल मनी ट्रांजेक्शन' ने महिलाओं के लिए वित्तीय लेन- देन को अधिक सुविधाजनक और लचीला बना दिया है। 'इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया' की 2022 की रपट' अनुसार, डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी में सुधार से 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सौ अरब डालर की वृद्धि हो सकती है। इस संभावित वृद्धि का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को होगा, क्योंकि डिजिटल मंच उन्हें कौशल विकास, रोजगार और उद्यमशीलता के नए अवसर प्रदान करते हैं।

डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या हर साल लगभग 2.5 फीसद की दर से बढ़ रही है। इससे न केवल महिलाएं 'स्टार्टअप्स' में भागीदारी कर रही हैं, बल्कि वे नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा दे रही हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। इसने उन्हें आनलाइन मंचों पर अपने छोटे व्यवसायों को विस्तार देने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद द की है। । रपटों के मुताबिक जिन महिलाओं के की पहुंच वे लगभग 140 फीसद अधिक आय अर्जित करती हैं। इंटरनेट उपभोग बढ़ाने के प्रयासों में 'डिजिटल डिवाइड' खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए, इन प्रयासों में महिलाओं और लड़कियों को इंटरनेट से होने वाली परेशानियों पर भी विचार करना चाहिए। भारत सरकार ने अपने 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत में डिजिटल पहुंच और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसे उद्योग दिग्गजों द्वारा इस पहुंच में तेजी लाई गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए डेटा इन मुद्दों पर हमारी प्रगति के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन यह भी जांचना महत्त्वपूर्ण है कि अपनाए गए दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक मानदंडों और संरचनाओं को मजबूत नहीं करते, जो असमानताएं बढ़ाते हैं।

'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य 'डिजिटल डिवाइड' को समाप्त करना है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाएं पूरी तरह अवसरों से लाभ उठा सकें। महिलाओं के लिए डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे इंटरनेट का उपयोग सुरक्षित और सशक्त रूप से कर सकें।

# पेजों से लेकर लोगों तक: सफल होने के लिए लेखकों को मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों है

विजय गर्ग

लेखन को अक्सर एक अकेले शिल्प के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज के प्रकाशन परिदृश्य में सफलता एक महान पांडुलिपि से कहीं अधिक की मांग करती है। चाहे आप एक महत्वाकांक्षी लेखक हों या एक स्थापित लेखक, आपके काम को व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली और प्रसिद्ध कृति में बदलने के लिए मार्केटिंग महत्वपूर्ण है। यहां बताया गया है कि लेखकों को सफल होने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों है:

**1. भीड़ भरे बाज़ार में दृश्यता**

प्रकाशन उद्योग संतृप्त है, हर साल लाखों पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। मार्केटिंग लेखकों को उनके लक्षित दर्शकों तक पहुंचकर और उनके काम के बारे में जागरूकता पैदा करके अलग दिखने में मदद करती है। मार्केटिंग के बिना, सबसे शानदार पुस्तकों के भी भीड़ में खो जाने का जोखिम रहता है।

**2. एक व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण**

पाठक लोगों से उतना ही जुड़ते हैं जितना वे कहानियों से जुड़ते हैं। एक लेखक का अनोखा ब्रांड - सोशल मीडिया, साक्षात्कार, ब्लॉग और घटनाओं के माध्यम से तैयार किया गया - एक व्यक्तिगत संबंध बनाता है जो पाठकों को अपनी ओर खींचता है। मार्केटिंग लेखकों को अपनी यात्रा, आवाज और मूल्यों को साझा करने, अपने दर्शकों के बीच वफादारी और विश्वास बनाने की अनुमति देती है।

**3. आधुनिक प्लेटफार्मों का लाभ उठाना**

इंस्टाग्राम और टिकटॉक से लेकर पॉडकास्ट और न्यूजलेटर तक, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किताबों की खोज के तरीके को बदल दिया है। मार्केटिंग लेखकों को इन प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, वायरल क्षण बनाने और वास्तविक समय में प्रशंसकों के साथ जुड़ने के लिए उपकरणों से लैस करती है।

**4. ड्राइविंग बुक बिक्री**

मार्केटिंग रणनीतियाँ जैसे पुस्तक लॉन्च, ईमेल अभियान और प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग सीधे बिक्री में योगदान करते हैं। यहां तक कि परंपरागत रूप से प्रकाशित लेखकों से भी अपने प्रकाशकों के साथ सक्रिय रूप से अपने काम को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

**5. दीर्घकालिक कैरियर के अवसर पैदा करना**

अच्छी मार्केटिंग सिर्फ किताबें नहीं बेचती-यह करियर बनाती है। मजबूत विपणन कौशल वाले लेखक अधिक अवसरों को आकर्षित करते हैं, जिनमें बोलने की व्यस्तता, अनुकूलन और सहयोगी परियोजनाएं शामिल हैं। मार्केटिंग लेखकों को उनके क्षेत्र में विचारशील नेताओं और रचनात्मक आवाज़ों के रूप में स्थापित करती है।

**6. प्रकाशन की गतिशीलता में बदलाव**

स्व-प्रकाशन ने इंडी लेखकों के लिए विपणन को गैर-परक्राम्य बना दिया है। यहां तक कि पारंपरिक सौदों वाले लोगों के लिए भी, प्रकाशक अक्सर खुद को प्रभावी ढंग से बाजार में उतारने की सिद्ध क्षमता वाले लेखकों के लिए संसाधनों को प्राथमिकता देते हैं।

**7. पाठक सहभागिता और प्रतिक्रिया**

विपणन लेखकों और पाठकों के बीच दोतरफा संबंध को बढ़ावा देता है। गुड्रेड्स, बुक क्लब और इंटरैक्टिव सोशल मीडिया अभियान जैसे प्लेटफ़ॉर्म पाठकों को क्या पसंद है, इसकी जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे लेखकों को अपनी कला को निखारने और अपने दर्शकों को बढ़ाने में मदद मिलती है।

**निष्कर्ष**

महान लेखन सफलता की नींव रखता है, लेकिन मार्केटिंग वह पुल है जो आपके काम को दुनिया से जोड़ता है। जो लेखक मार्केटिंग को अपनाते हैं, वे अपनी आवाज को बढ़ाते हैं, अपने पाठकों की संख्या बढ़ाते हैं और अपने जुनून को एक स्थायी करियर में बदल देते हैं। चाहे वह सोशल मीडिया पर महारत हासिल करना हो, लक्षित विज्ञापन अभियान चलाना हो, या साहित्यिक प्रभावशाली लोगों के साथ साझेदारी करना हो, मार्केटिंग वह उत्प्रेरक है जो एक किताब को एक आंदोलन में बदल देता है।

**सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब**

# वृद्ध पशुओं के संरक्षण का महत्व

विजय गर्ग

जीव-जंतुओं का संरक्षण आज के समय में पर्यावरणीय चिंताओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। परंतु देखा गया है कि यह चर्चा अक्सर विलुप्तप्राय प्रजातियों और उनके बचाव तक ही सीमित रहती है। वृद्ध जानवरों के संरक्षण का महत्व, जो उनके झुंड या समाज में मार्गदर्शक और संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, आमतौर पर उपेक्षित रह जाता है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि बूढ़े और बुद्धिमान जानवर अपने समूहों एवं पर्यावरण में स्थायित्व बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी यह जरूरी है।

मानवीय गतिविधियों के कारण न केवल वृद्ध व बुद्धिमान जीवों की संख्या में गिरावट आ रही है, बल्कि उनके साथ पर्यावरणीय और जैविक जानकारियां भी विलुप्त हो रही हैं। हालिया अध्ययन चार्ल्स डार्विन विवि, आस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किया गया है और इसे साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि वृद्ध व बुद्धिमान जानवर जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

हाथी, व्हेल, बंदर और अन्य लंबे समय तक जीने वाली प्रजातियां अपने समूह के लिए अनुभवजन्य ज्ञान का स्रोत होते हैं, जो उनकी संतानों और समुदाय के लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के तौर पर, वृद्ध हाथियों ( मैट्रियार्क्स ) को सूखे के समय जल स्रोतों का पता लगाने और समूह की सुरक्षा का मार्गदर्शन करने में कुशल माना जाता है। इसी तरह वृद्ध व्हेल अपनी संतानों को भोजन प्राप्त करने एवं जटिल समुद्री वातावरण में नेविगेट करने का प्रशिक्षण देती हैं। विशेष रूप से मनुष्यों में, दादी-नानी जैसी संरचनाओं का प्रभाव संतानों के जीवित रहने और उनकी प्रजनन क्षमता पर भी देखा गया है। इसी तरह मछलियों और ठंडे खून वाले जीवों में वृद्ध और बड़े जीव लंबे समय तक प्रजनन कर सकते हैं और अपनी संतानों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कई जानवरों के समूहों में वृद्ध सदस्य नेतृत्व और निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे युवा सदस्यों को प्रशिक्षित करते हैं।

वृद्ध जीवों की घटती संख्या के लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। अवैध शिकार और मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार इन प्रजातियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास की कमी और बीमारियां भी इन जीवों की संख्या को प्रभावित कर रही हैं। वृद्ध जीव न केवल अपने समूह के लिए बल्कि मानव समाज और प्रकृति के लिए भी अनमोल हैं। उनके अनुभव और ज्ञान को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो इसके परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए भयावह हो सकते हैं। इसलिए वृद्ध जानवरों को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह प्रकृति और मानवता के हित में भी है।

*सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब*

# सोशल मीडिया के निशान

विजय गर्ग

आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, खासकर बच्चों और युवा वयस्कों के लिए। हालाँकि ये प्लेटफॉर्म संचार, आत्म-अभिव्यक्ति और सूचना तक पहुंच के लिए ढेर सारे लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से शरीर की छवि के संदर्भ में। सोशल मीडिया पर सावधानी से तैयार की गई और अक्सर अवास्तविक छवियों की लगातार बाढ़ सुंदरता की विकृत धारणा पैदा करती है, जिससे अपर्याप्तता, असुरक्षा और कम आत्मसम्मान की भावनाएं पैदा होती हैं। युवा व्यक्तियों पर ऐसे संदेशों की बौछार की जाती है जो शारीरिक उपस्थिति को मूल्य के बराबर मानते हैं, जिससे पूर्णता की निरंतर खोज को बढ़ावा मिलता है जिसे कभी भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक अप्राप्य आदर्श की यह निरंतर खोज खाने के विकार, चिंता और अवसाद सहित गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। अवास्तविक सौंदर्य मानकों के अनुरूप होने का दबाव व्यक्तियों को अत्यधिक आहार, व्यायाम और यहां तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे अस्वास्थ्यकर व्यवहार में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। शरीर की छवि पर सोशल मीडिया का प्रभाव इन प्लेटफार्मों में व्याप्त तुलना की संस्कृति से और भी बढ़ गया है। युवा व्यक्ति लगातार अपनी तुलना अपने साथियों से करते हैं, जिससे अक्सर उनमें ईर्ष्या, असंतोष और बेकार की भावनाएँ पैदा होती हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर गुमनामी और जवाबदेही की कमी व्यक्तियों को साइबरबुलिंग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे युवा उपयोगकर्ताओं के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंच सकता है। नकारात्मक टिप्पणियों और आहत करने वाली टिप्पणियों का लगातार संपर्क स्थायी निशान छोड़ सकता है, जिससे सामाजिक अलगाव, अलगाव और यहां तक कि आत्म-विनाशकारी व्यवहार भी हो सकता है।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना चाहिए, छात्रों को ऑनलाइन सामने आने वाली छवियों का गंभीर मूल्यांकन करना और सोशल मीडिया चित्रण की अवास्तविक प्रकृति को पहचानना सिखाना चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को आत्म स्वीकृति, शरीर की सकारात्मकता और स्वस्थ आत्म-सम्मान के महत्व के बारे में बच्चों और युवा वयस्कों के साथ खुली और ईमानदार बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्हें उनकी शारीरिक बनावट के बजाय उनकी शक्तियों, मूल्यों और जुनून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकार को साइबरबुलिंग के खिलाफ सख्त नीतियां भी लागू करनी चाहिए और विविधता और समावेशिता का जश्न मनाने वाले शरीर सकारात्मकता अभियानों को बढ़ावा देना चाहिए। युवा व्यक्तियों को अपने सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति सचेत रहना और आवश्यक होने पर इन प्लेटफार्मों से ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करना एक कठिन काम होगा। लेकिन हमें ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो आत्म स्वीकृति को बढ़ावा दें, जैसे शौक पूरा करना, प्रकृति में समय बिताना और आत्म- देखभाल प्रथाओं में संलग्न होना ।

आत्म-स्वीकृति, आलोचनात्मक सोच और खुले संचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम बच्चों और युवा वयस्कों को लचीलेपन और सकारात्मक आत्म - छवि के साथ डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे लंबे समय में उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो सके।

# क्यों ज़रूरी है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ?

विजय गर्ग

विवाह के बाद कई दंपती विवाह प्रमाणपत्र नहीं बनवाते। परंतु यह एक कानूनी दस्तावेज़ है जो पति-पत्नी दोनों के विवाह का वैध प्रमाण होता है। यह न केवल विवाह की पंजीकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, बल्कि विवाह संबंधी अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से विवाह पंजीकरण को अनिवार्य घोषित किया।

मैरिज सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए ? विवाह के बाद जो लड़कियां अपना सरनेम नहीं बदलतीं, उनके लिए यह दस्तावेज़ विवाह का क़ानूनी सबूत प्रदान करता है। विदेश में वीज़ा और इमिग्रेशन प्रक्रियाओं में पति/पत्नी के रिश्ते को प्रमाणित करने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है। बैंक जमा या जीवन बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, ख़ासकर जब नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं हो । पेंशन योजनाओं और अन्य वित्तीय लाभों का दावा करने के लिए भी सर्टिफिकेट आवश्यक है। तलाक़, संपत्ति विवाद और उत्तराधिकार के मामलों में विवाह की वैधता साबित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यदि पति- पत्नी के सरनेम अलग हैं, तो बच्चों की वैधता प्रमाणित करने में यह सहायक होता है । मैरिज सर्टिफिकेट विवाह से संबंधित धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से महिलाओं की रक्षा करता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यदि विवाह प्रमाणपत्र नहीं होगा ... जिन पति-पत्नी की विदेश में साथ रहने या जाने की योजना है उनके लिए विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में वीज़ा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

बैंक जमा, जीवन बीमा या कर्मचारी बीमा पेंशन योजना के तहत, एक विवाहित व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद लाभ के लिए केवल अपनी पत्नी और बच्चों को नामांकित कर सकता है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के इन लाभों का दावा करना मुश्किल हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और पैतृक संपत्ति पर महिला के अधिकारों और हितों के दावे को सामान्यतः विवाह की वैधता के आधार पर चुनौती दी जाती है। मैरिज सर्टिफिकेट न होने की स्थिति में महिला अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकेगी। वैवाहिक विवादों या तलाक़ की स्थिति में, मैरिज सर्टिफिकेट न होने के कारण विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में बिना पंजीकरण और रीति-रिवाजों के किए गए विवाह को अमान्य करार दिया गया था। कई मामलों में, बिना रीति-रिवाजों के विवाह करने या धर्मस्थल में विवाह कर धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में, शिक्षित होने के बावजूद, महिलाएं विवाह प्रमाणपत्र के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।

# दुनियाभर के लिए रोडमैप बन सकता है 'प्रगति' का मोदी मॉडल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया सुझाव

परिवहन विशेष न्यूज

ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रगति मंच ने डिजिटल गवर्नेंस के लिहाज से काफी अहम तरक्की की है। इसने बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में अहम भूमिका निभाई। प्रगति प्लेटफॉर्म ने सरकारी स्तरों पर सहयोग को सुगम बनाया।

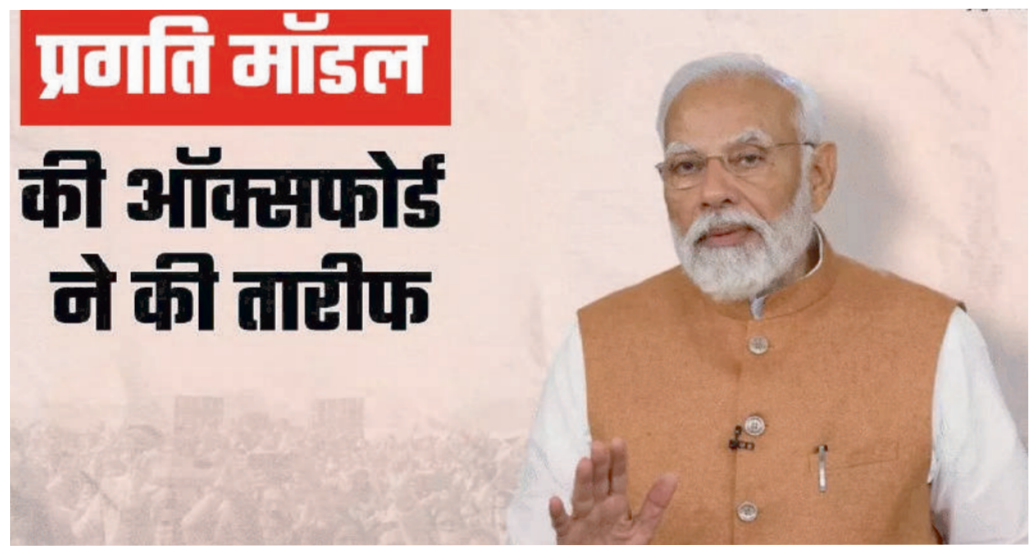


**नई दिल्ली।** भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास का जो मॉडल अपनाया है, वह विश्व के अन्य विकासशील देशों के नेताओं के लिए भी रोडमैप बन सकता है।

इंग्लैंड के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और गेट्स फाउंडेशन के अध्ययन में दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने बड़ी विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए जो डिजिटल प्लेटफार्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) को अपनाया है, उससे न सिर्फ दशकों से लटके बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए, बल्कि नेतृत्व के इस तौर-तरीके से प्रधानमंत्री ने कार्य संस्कृति को बदलते हुए विश्व के नेताओं को एक दिशा दिखाई है।

"फ्रॉम ग्रिडलाक टू ग्रोथ"" शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में केस स्टडी के तौर पर 17.05 लाख करोड़ रुपये लागत के उन 340 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। इनकी प्रगति की नियमित समीक्षा प्रगति प्लेटफार्म और सतत बैठकों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने की। इनमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, जो कि दशकों से लटके हुए थे।

**कैसे काम करता है सरकार प्रगति प्लेटफॉर्म**

दरसअल, गुजरात में भूकंप के बाद वहां विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने स्वागत नाम से जो पहल वहां की थी, उसे ही प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति नाम से 2015 में शुरू किया। इसके जरिये प्रोजेक्ट की रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। इसकी बैठक हर महीने होती है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बैठक में किन-किन प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी, ये पहले से तय होता है।

संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रगति का ब्योरा रखते हैं। पीएम मोदी समीक्षा करने के बाद दिशा-निर्देश देते हैं। प्रगति के माध्यम से समयबद्ध पूरी हुई परियोजनाओं में असम के बोगीबील पुल, जम्मू-ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक, बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ओडिशा का हरिदासपुर-पारादीप रेल कनेक्शन आदि का उदाहरण दिया गया है।

साथ ही अध्ययनकर्ताओं ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में रखे गए 11.8 प्रतिशत पूंजीगत व्यय को जिस तरह से बढ़ाकर 2023-24 तक 22.2 प्रतिशत पर पहुंचाया है, उसका न सिर्फ जीडीपी पर असर हुआ है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

**प्रगति के महत्वपूर्ण बिंदु**

विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक इन्फ्रा परियोजनाओं में क्रांतिकारी बदलाव आया।

सरकार में शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता का असर पड़ा और ग्राउंड जीरो तक टीम वर्क दिखाई दिया। समस्याओं की सतत निगरानी होने के चलते उनका समाधान भी लगातार होता गया।-

प्रगति के साथ कई डिजिटल प्लेटफार्म को जोड़ने से डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम तैयार हुआ।

प्रगति का असर सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर भी पड़ा, जिससे आमजन को गुणवत्तायुक्त जीवन का अवसर मिला।

केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने से परियोजनाओं में होने वाला बेवजह का विलंब खत्म हुआ।

भारत अब विश्व को डिजिटल गवर्नेंस का पाठ पढ़ाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है।

## बाजार की अनिश्चितता से मुकाबला : कम-अस्थिरता वाले पोर्टफोलियो राहत देने में सक्षम

बाजार से प्रेरित चिंता के बिना लॉन्गटर्म वेल्थ क्रिएशन की चाहत रखने वाले निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एनएफओ में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड है। 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक निवेश के लिए खुला एनएफओ अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और हाई कैश फ्लो वाली लार्ज-कैप कंपनियों पर केंद्रित है। आइए जानते हैं इस एनएफओ में क्या खास है।

**नई दिल्ली।** जबकि भारत का लॉन्गटर्म आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, अच्छे खासे मूल्य वाले इक्विटी बाजारों में तनाव के संकेत दिखने लगे हैं। अक्टूबर से, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि एसएंडपी मिडकैप और स्मॉल कैप सूचकांक क्रमशः 7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत नीचे हैं।

वैश्विक और घरेलू कारक अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति में ढील दी है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है, बढ़ती खाद्य कीमतों से प्रेरित मुद्रास्फीति अपने लक्ष्य से ऊपर वापस आ गई है। इससे अपेक्षित दर कटौती में देरी हो सकती है, जिससे घरेलू विकास पर और दबाव पड़ सकता है। भू-राजनीतिक तनाव ने भी निवेशकों के विश्वास को हिला दिया है, विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर से 12.5 बिलियन डॉलर से अधिक की निकासी की है।

निवेशकों के लिए, यह सुधार अस्थिर रहा है, खासकर वर्षों के मजबूत इक्विटी बाजार प्रदर्शन के बाद, ये महसूस किया जा रहा है। लंबी अवधि में दृष्टिकोण बनाए रखना और बाजार में उतार-चढ़ाव को सहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कम-अस्थिरता वाली इक्विटी रणनीति एक समाधान प्रदान करती है, जो निवेशकों को जोखिम का प्रबंधन करते हुए बाजार में बने रहने में मदद करती है।

बेहतर प्रशासन, उच्च पूंजी तरलता और उचित मूल्यांकन के लिए जाने जाने वाले लार्ज-कैप स्टॉक, मिड या स्मॉल कैप की तुलना में अस्थिरता के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। हाल ही में एफआईआई की बिक्री का खामियाजा लार्ज कैप को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए वे उलटफेर देख सकते हैं, जिससे लाभ के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा, निवेशक लार्ज-कैप यूनिवर्स के भीतर सबसे कम अस्थिर स्टॉक की पहचान करने के लिए अस्थिरता फिल्टर लागू करके लाभ उठा सकते हैं, और इसे कम जोखिम के लिए अपने पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय प्रबंधन और फंडामेंटल रिसर्च के साथ जोड़ सकते हैं।

# समझदारी से निवेश करें, तनाव मुक्त रहें: इक्विटी वैरिएंस फंड के साथ बाजार में उतार-चढ़ाव से बचें

परिवहन विशेष न्यूज

मिनिमम वैरिएंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित इक्विटी फंड निवेशकों को बाजार की अस्थिरता के दौरान एक सहज सवारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वैरिएंस औसत से रिटर्न के डेविएशन को मापता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एक नया फंड ऑफर (एनएफओ) लेकर आया है- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड। यह 18 नवंबर से 02 दिसंबर 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है।

**नई दिल्ली।** नवंबर का महीना निवेशकों के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा है, जिसमें कई कारकों के कारण घरेलू इक्विटी बाजार में गिरावट आई है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी चुनाव और भारत में आगामी राज्य चुनावों के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली शामिल है।

अक्टूबर और इस महीने के दौरान, घरेलू इक्विटी इकोसिस्टम को काफी मजबूत करने वाले एफआईआई ने 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक की एसेट्स बेची, जिससे बाजार में भारी गिरावट आई। इस तनावपूर्ण माहौल में, निवेशक ऐसे निवेश चैनल की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें ऐसे अस्थिर चरणों के दौरान मन की शांति प्रदान करे।

**आपको कौन सा इक्विटी फंड चुनना चाहिए?**

मिनिमम वैरिएंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित इक्विटी फंड निवेशकों को बाजार की अस्थिरता के दौरान एक सहज सवारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वैरिएंस औसत से रिटर्न के डेविएशन को मापता है, और हाई वैरिएंस अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव की तरफ संकेत करता है। हवाई अड्डे तक आने-जाने की कल्पना करें: यदि औसत समय एक घंटा है, लेकिन ट्रैफिक इसे 1.5 घंटे या 45 मिनट तक कम कर सकता है, तो यात्रा अनिश्चित हो जाती है।

इसी तरह, निवेश में, भिन्नता को कम करने का मतलब है रिटर्न में इस तरह के अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को कम करना। कम अस्थिरता वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करके और स्थिर कंपनियों में निवेश को फैलाकर, ये फंड निवेशकों के लिए मानसिक शांति सुनिश्चित करते हुए स्थिर, जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं।

**मिनिमम वैरिएंस के साथ स्थिरता प्राप्त करना**

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एक नया फंड ऑफर (एनएफओ) लेकर आया है- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड। यह 18 नवंबर से 02 दिसंबर, 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। इक्विटी मिनिमम वैरिएंस सिद्धांत का पालन करने वाला यह फंड मुख्य रूप से निफ्टी 50 इंडेक्स की कम अस्थिरता वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करता है।

स्थिर शेयरों को अधिक महत्व देकर और अत्यधिक अस्थिर शेयरों में जोखिम को कम करके, ये फंड एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं, भले ही कठोर विश्लेषण और वेटेज-आधारित आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि पोर्टफोलियो विविधतापूर्ण हो, फिर भी अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से संतुलित रहे। बाजार में उतार-चढ़ाव के बारे में चिंतित निवेशकों के लिए, इक्विटी वैरिएंस फंड एक विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अप्रत्याशित बाजार उतार-चढ़ाव के

# कहां से लेना चाहिए गोल्ड लोन, किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

परिवहन विशेष न्यूज

गोल्ड को मुश्किल वक्त का साथी कहते हैं क्योंकि इसे आप अपनी जरूरत के वक्त बेचकर या गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। सोने पर वित्तीय संस्थान जल्दी और कम ब्याज दर पर कर्ज भी दे देते हैं। यह सबसे सिक्योर्ड लोन भी समझा जाता है। आइए जानते हैं कि आपको गोल्ड लोन कहां से लेना चाहिए और रीपेमेंट का विकल्प कैसे चुनना चाहिए।

**नई दिल्ली।** पर्सनल लोन सेगमेंट में इन दिनों गोल्ड लोन काफी तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों में गोल्ड लोन में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 50.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जानकारों का कहना है कि गोल्ड लोन लेने के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखने पर ग्राहक उसे आसानी से चुका भी सकता है और उसका सोना भी उसे सही सलामत वापस मिल जाएगा। गोल्ड लोन की अवधि छोटी होती है। अमूमन यह तीन माह से लेकर तीन साल तक के लिए लिया जाता है।

**गोल्ड लोन चुकाने के विकल्प**

बड़े बैंक गोल्ड लोन उतारने के लिए इक्विटेड मंथली इंस्टालमेंट (ईएमआई) के साथ एकमुश्त भुगतान का भी विकल्प देते हैं। हालांकि कई एनबीएफसी अभी गोल्ड लोन चुकाने के लिए ईएमआई की सुविधा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को लोन चुकाने के लिए ईएमई की सहूलियत देने के लिए कहा है।

अभी आम तौर पर अभी गोल्ड लोन की वापसी छह माह या एक साल के बाद मूलधन और ब्याज दोनों को एकमुश्त चुकाकर किया जाता है। इसे बुलेट पेमेंट विकल्प कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि गोल्ड लोन लेने वाला वेतन भोगी है तो उसे लोन चुकाने के लिए ईएमआई का विकल्प चुनना चाहिए।

**बुलेट पेमेंट किसके लिए अच्छा?**

कई बैंक ईएमआई पर लोन चुकाने पर अधिक अवधि के लिए भी गोल्ड लोन दे देते हैं। जो खुदरा व्यापारी है वह गोल्ड लोन चुकाने के लिए रोज के भुगतान का भी विकल्प चुन सकते हैं। जिनकी कमाई मौसमी (सीजनल) होती है, उन्हें बुलेट पेमेंट विकल्प चुनना चाहिए। जानकारों का यह भी कहना है कि ईएमआई मासिक कमाई का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे डिफॉल्टर होने का खतरा कम रहता है।

वित्तीय सलाहकार फर्म हम फौजी इनिशिएटिव के सीईओ संजीव गोविल कहते हैं कि गोल्ड लोन प्रमुख व नामी वित्तीय संस्थाओं से ही लेना चाहिए। गोल्ड लोन की बढ़ती मांग को देखते हुए छोटी-मोटी कंपनियां भी इस काम में कूद पड़ी है। इस प्रकार की कंपनियां लोन चुकाने के बाद भी सोना वापस लौटाने में ग्राहक को टरकाने की नीति अपनाते हैं।

कई बार सोना बदलने की शिकायत देखने को मिलती है। ये कंपनियां मासिक 2-2.5 प्रतिशत पर गोल्ड लोन देने की पेशकश करती है जो सालाना 30 प्रतिशत तक चला जाता है।

# सोना हुआ सस्ता, चांदी के भी गिरे दाम; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले हफ्ते कॉमेक्स गोल्ड कमजोर नोट पर बंद हुआ क्योंकि इजरायल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम समझौते के बाद सुरक्षित निवेश समझे जाने वाले सोने की मांग कम हो गई। साथ ही मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताओं ने अगले साल दरों में कटौती की गति के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। इस वजह से भी कारोबारी सोने की खरीद नहीं बढ़ा रहे हैं।

**नई दिल्ली।** सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुख के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 200 रुपये गिरकर 79,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। शुक्रवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई।

औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से कमजोर उठान के कारण चांदी भी 2,200 रुपये गिरकर 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 92,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 200 रुपये गिरकर 78,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। शुक्रवार को यह कीमती धातु 79,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई।

इस बीच, एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 478 रुपये या 0.63 प्रतिशत गिरकर 75,896 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी के अनुबंध 574 रुपये या 0.65 प्रतिशत गिरकर 88,307 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। दिन के कारोबार के दौरान मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सिल्वर 1,081 रुपये या 1.22 प्रतिशत गिरकर 87,800 रुपये प्रति किलोग्राम के निचले स्तर पर आ गई।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के एवीपी - कमोडिटीज एंड करेंसीज, मनीष शर्मा ने कहा, ₹यह गिरावट अमेरिकी डॉलर में आई रिकवरी के कारण हुई। इसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ से जुड़ी मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से बढ़ावा मिला।

कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी-कमोडिटी रिसर्च, कायनात चैनवाला के अनुसार, पिछले हफ्ते कॉमेक्स गोल्ड कमजोर नोट पर बंद हुआ क्योंकि इजरायल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम समझौते के बाद सुरक्षित निवेश समझे जाने वाले सोने की मांग कम हो गी। चैनवाला का कहना है कि लगातार मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं ने अगले साल दरों में कटौती की गति के बारे में संदेह पैदा कर दिया है।

एबन्स होल्डिंग्स के सीईओ चिंतन मेहता ने कहा,₹व्यापारी यूक्रेन-रूस के बीच बढ़ते तनाव पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उनकी नजर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा पर भी रहेगी। इसके अलावा फेडरल रिजर्व (फेड) के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल सहित फेड अधिकारियों के प्रमुख संबोधन भी ध्यान में हैं, क्योंकि बाजार दिसंबर में ब्याज दर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।₹

मेहता ने कहा कि हालांकि पिछले स्तरों की तुलना में सोने में भागीदारी कम हुई है, लेकिन निवेशकों द्वारा निवेश बढ़ाने के कारण कीमतें मजबूत हो सकती हैं। व्यापारियों का मानना है कि सोने की कीमतें और बढ़ेंगी। हालांकि अतिरिक्त ब्याज दर कटौती में संभावित देरी से निकट अवधि में गिरावट हो सकती है, जो निवेशकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है।

# अपने स्केल्स को फिर से संतुलित करें- मिनिमम वैरिएंस वाले इक्विटी फंड जोखिम-झुकाव वाले पोर्टफोलियो का मुकाबला करने में सक्षम

आज के बाजार में पोर्टफोलियो संतुलित रिटर्न के बजाय जोखिम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। धीमी आय वृद्धि उच्च मूल्यांकन उतार-चढ़ाव वाले एफपीआई प्रवाह और भू-राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दे जोखिम-रिवॉर्ड बिनेस को और अधिक जटिल बनाते हैं। पारंपरिक इक्विटी फंड इन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकते हैं जिससे मिनिमम वैरिएंस वाले फंड बनते हैं जो कम आपको बेहतर रिटर्न देते हैं।

**नई दिल्ली।** निवेश में, दैनिक जीवन की तरह, केवल औसत पर निर्भर रहना भ्रामक हो सकता है - 6 फुट लंबे एक व्यक्ति का उदाहरण लें जो 5 फीट की औसत गहराई वाली नदी को पार करते समय डूब गया। नदी के कुछ हिस्से औसत से अधिक गहरे थे, जिससे अप्रत्याशित जोखिम पैदा हुआ।

इसी तरह, औसत रिटर्न पर आधारित एक निवेश पोर्टफोलियो इन औसत से डेविएशन पर विचार नहीं कर सकता है, जिससे कमी हो सकती है। इक्विटी फंड में वैरिएंस को समझना और कम करना एक सहज प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है, खासकर अस्थिर बाजारों के दौरान, औसत आंकड़ों के भ्रामक आराम का मुकाबला करते हुए।

लंबी अवधि की निवेश योजना में वैरिएंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - कल्पना करें कि आप 25 साल में रिटायर होने की योजना बनाते हैं और आपको 5.7 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आप 13 प्रतिशत के औसत ऐतिहासिक रिटर्न के आधार पर अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद करते हुए एसआईपी के माध्यम से हर महीने 25,000 रुपये का निवेश करते हैं।

हालांकि, अप्रत्याशित घटनाओं या 10 प्रतिशत के कम वास्तविक रिटर्न के कारण, आपका निवेश केवल 3.3 करोड़ रुपये तक बढ़ता है। यह विसंगति वैरिएंस को ध्यान में रखे बिना औसत पर निर्भर रहने के जोखिम को उजागर करती है। बाजार में गिरावट, भू-राजनीतिक तनाव और आपातकालीन निकासी जैसे कारक महत्वपूर्ण डेविएशन पैदा कर सकते हैं, जो अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं।

आज के बाजार में, पोर्टफोलियो संतुलित रिटर्न के बजाय जोखिम की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, धीमी आय वृद्धि, उच्च मूल्यांकन, उतार-चढ़ाव वाले एफपीआई प्रवाह और भू-राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दे जोखिम-रिवॉर्ड बिज़नेस को और अधिक जटिल बनाते हैं।

पारंपरिक इक्विटी फंड इन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर सकते हैं, जिससे मिनिमम वैरिएंस वाले फंड बनते हैं, जो कम अस्थिरता वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित करके और स्थिर कंपनियों में निवेश फैलाकर आवंटन को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने और जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन फंडों का उद्देश्य निवेशकों के लिए मन की शांति सुनिश्चित करते हुए स्थिर, रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न प्रदान करना है।

इस को देखते हुए, निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की नई पेशकश, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वैरिएंस फंड पर विचार कर सकते हैं, जो 18 नवंबर से 2 दिसंबर, 2024 तक निवेश के लिए उपलब्ध है।

यह योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जो बाजार में उतार-चढ़ाव को कम करते हुए लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि और इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं, जिसमें मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन और मजबूत नकदी प्रवाह के लिए जानी जाने वाली लार्ज-कैप कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रणनीति कम अस्थिरता वाले लार्ज-कैप शेयरों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए विश्लेषण और वेटेज प्रबंधन का उपयोग किया जाता है।

# सिगरेट और तंबाकू लेने वालों को लगने वाला है झटका, जीएसटी में होगा इजाफा; रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें

जीएसटी पर बने मंत्रिसमूह ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों सिगरेट तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारिक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर बढ़ाने का फैसला किया। मंत्रिसमूह कुल 148 वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। इसका शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

**नई दिल्ली।** जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने सोमवार को कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू और इससे संबंधित हानिकारिक उत्पादों पर कर की मौजूदा दर 28 प्रतिशत को बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का फैसला किया। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है।

**रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें**

एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले जीओएम ने अपैरल पर भी कर की दरों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। जीओएम के फैसले के अनुसार, अब 1,500 रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत, 1,500 से 10 हजार रुपये तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत और 10 हजार से अधिक मूल्य वाले गारमेंट्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

**148 वस्तुओं पर कर की दरों में हो सकता बदलाव**

अधिकारी ने बताया कि मंत्रिसमूह कुल 148 वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। इसका शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा। मंत्रिसमूह की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। करों में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को ही लेना है।

**तंबाकू जैसे उत्पादों के लिए बनेगा नया स्लैब**

अधिकारी ने बताया कि तंबाकू और इससे संबंधित उत्पादों पर 35 प्रतिशत कर के लिए अतिरिक्त स्लैब बनाया जाएगा। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर के स्लैब पहले की तरह जारी रहेंगे। जीएसटी काउंसिल में पेश करने के लिए मंत्रिसमूह ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। जीओएम ने अक्टूबर में कई वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था। इसमें 20 लीटर या इससे ज्यादा क्षमता वाली पीने के पानी की बोतल पर कर की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना प्रमुख है।

जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला मंत्रिसमूह मांगेगा और समयअधिकारी ने बताया कि जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर गठित मंत्रिसमूह ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह माह का समय और मांगने का फैसला किया। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता वाले इस मंत्रिसमूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल के सदस्य भी शामिल हैं।

# अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग भवन पर हमला, भारत ने जताया खेद; यूनुस सरकार ने याद दिलाया विएना समझौता

भारत ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और देश में अन्य राजनयिक परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। इससे पहले दिन में अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग परिसर में सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के परिसर में हुई घटना बेहद खेदजनक है।

**नई दिल्ली।** सोमवार को अगरतला स्थिति बांग्लादेश के उप उच्चायोग के भवन पर कुछ असमाजिक तत्वों की तरफ से किए गए हमले पर भारत ने गहरा खेद जताया है। साथ ही इस भवन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उधर, बांग्लादेश ने इस मुद्दे को उठाया है और बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारत को विएना समझौते की याद दिलाई है।

**भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव गहराया**

इस हमले ने भारत को बैक-फुट पर ला दिया है क्योंकि अभी तक भारत ढाका स्थित अपने उच्चायोग की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाए हुए था। इस प्रकरण से भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा कूटनीतिक तनाव और गहरा गया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर बताया है कि, "आज दिन में अगरतला स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के भवन पर किया गया हमला काफी खेदजनक है। किसी भी सूरत में कूटनयिकों और कांसुलर की परिसंपत्तियों पर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग और देश के दूसरे हिस्सों में उप उच्चायोगों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा बढ़ा रही है।"

**भवन का एक हिस्सा तोड़ा**

विदेश मंत्रालय के इस बयान से कुछ घंटे पहले ही हजारों लोगों की भीड़ ने जुलूस के रूप में बांग्लादेश में हिंदु धर्मगुरू चिन्मय कृष्णा दास व उनके अनुयायियों के पकड़े जाने के खिलाफ उप उच्चायोग के भवन की तरफ मार्च किया था। बताया जा रहा है कि चार-पांच दर्जन लोगों ने भवन के एक हिस्से को तोड़ कर अंदर प्रवेश कर लिया था।

**भारत उठा चुका चिन्मय की गिरफ्तारी का मुद्दा**

यह भी सनद रहे कि पिछले शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर अपना क्षोभ व्यक्त किया था। उधर, बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि अगरतला में किया गया हमला विएना समझौते (1961) का उल्लंघन है। यह मेजबान देश का दायित्व है कि वह दूसरे देशों के राजनयिकों और उनकी परिसंपत्तियों की हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे।

**बांग्लादेश ने की जांच कराने की मांग**

बांग्लादेश ने कहा कि वह भारत सरकार से अपील करता है कि वह इस मामले की पूरी जांच कराए और बांग्लादेश के किसी दूसरे मिशन पर इस तरह का कोई और हमला नहीं होने दे। साथ ही बांग्लादेश के मिशन व उच्चायोग में काम करने वाले हर कर्मचारी और उनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान करे।

# कानूनी सहायता मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की सुविधा के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

देश के शीर्ष न्यायालय ने एक फैसले के दौरान अहम टिप्पणी की। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में स्वयं को बचाना और कानूनी सहायता प्राप्त करना अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर अभियुक्त को प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मुहैया कराई जाती है तो उसे अनुच्छेद 21 में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

**नई दिल्ली:** सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि आपराधिक मुकदमे में स्वयं को बचाना और कानूनी सहायता प्राप्त करना अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार उसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मिला है। अगर अभियुक्त को प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मुहैया कराई जाती है, तो उसे अनुच्छेद 21 में मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। सिर्फ नाम के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने का कोई मतलब नहीं है। कानूनी सहायता प्रभावी होनी चाहिए।

**कोर्ट ने जारी किया दिशा निर्देश**

कोर्ट ने यह बात दुष्कर्म और हत्या के एक दोषी को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी करते हुए कही है। साथ ही अभियुक्त को मुफ्त कानूनी सहायता दिए जाने और आपराधिक मुकदमे में लोक अभियोजक (सरकारी वकील) की भूमिका के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ये आदेश न्यायमूर्ति अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक मामले में 10 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी अशोक की सजा के खिलाफ दाखिल अपील स्वीकार करते हुए सुनाया। निचली अदालत ने अशोक को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि हाई कोर्ट ने मृत्युदंड को जीवन पर्यंत कैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई, 2022 को 13 साल जेल भुगतने के आधार पर उसे जमानत दे दी थी। इस मामले में अभियुक्त अशोक ने अपना कोई वकील नहीं किया था। उसे वकील सरकार की ओर से मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब गवाह के बयान दर्ज हुए उस समय अभियुक्त की ओर से कोई वकील नहीं था और आरोप तय होने के वक्त भी अभियुक्त का वकील नहीं था। साथ ही अभियुक्त से 313 के बयान के समय महत्वपूर्ण सामग्री नहीं रखी गई और न ही उससे संबंधित सवाल पूछे गए। और भी कई खामियां पाईं।

**असमर्थ अभियुक्त को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार**

कोर्ट ने अभियुक्त को संविधान में मिले मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकार का उल्लेख करते हुए कहा कि वकील रखने में असमर्थ अभियुक्त को रिमांड के समय से मुफ्त कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। यहां तक कि जमानत याचिका दाखिल करने के लिए भी अभियुक्त को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। पीठ ने कानूनी मदद मुहैया कराने और सरकारी वकील की भूमिका के बारे में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि अदालत का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त को प्रभावी कानूनी मदद मुहैया हो।

# 125 डिग्री तक झुकी थी रीढ़ की हड्डी, AIIMS में साढ़े तीन घंटे चला ऑपरेशन; अब पैरों पर सीधी खड़ी हो गई युवती

बचपन से झोलाछाप के चक्कर में आकर परिजनों ने बेटी को किसी बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाया। जब वह 19 साल की हो गई तो उसकी रीढ़ की हड्डी 125 डिग्री तक गई थी। इसके बाद युवती दिल्ली एम्स में पहुंची। वहीं एम्स में युवती का ऑपरेशन हुआ और तब वह सीधी खड़ी हो गई है। पढ़िए आखिर डॉक्टरों ने कैसे असंभव को संभव में बदल दिया।

**नई दिल्ली।** रीढ़ की जन्मजात विकृति कुबड़ (काइफोसिस) से पीड़ित एक 19 वर्षीय युवती के माता-पिता झोलाछाप के चक्कर में पड़ कर इस उम्मीद में बेटी के बड़े होने का इंतजार करते रहे कि उम्र बढ़ने के साथ वह खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी 125 डिग्री तक झुक गई।

इसके बाद वह इलाज के लिए एम्स पहुंची। जहां पिछले माह एक सप्ताह के अंतराल पर दो रीढ़ की हड्डी की दो जटिल सर्जरी हुई। इसके बाद युवती अपने पैरों पर सीधी खड़ी हो सकी।

**दिल्ली के कड़कड़डूमा की रहने वाली है कनिष्का**

पीड़ित युवती कनिष्का दिल्ली के कड़कड़डूमा की रहने वाली है। एम्स के आर्थोपेडिक सर्जरी के प्रोफेसर डॉ. भावुक गर्ग ने बताया कि जब वह एम्स में इलाज के लिए पहुंची तो रीढ़ की विकृति गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी थी। पीठ में दर्द रहता था और दैनिक कार्य में दिक्कत हो रही थी। एम्स में उसकी एक्सरे, एमआरआई व सीटी स्कैन व पीएफटी (पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट) जांच की गई।

वहीं, तब पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी आपस में सटी हुई थी और बीच के हिस्से से 125 डिग्री पर झुक गई थी। इस वजह से वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रही थी। रीढ़ को सीधा करने के लिए सर्जरी में छह से सात घंटा समय लगता। इतनी लंबी सर्जरी में स्पाइन कॉर्ड प्रभावित होने, सर्जरी के दौरान अधिक रक्त स्राव, पैरों में कमजोरी होने की आशंका जैसे जोखिम थे।

**सर्जरी में लगा साढ़े तीन घंटे का समय**

क्योंकि सर्जरी के दौरान मरीज की रीढ़ को दो जगहों पर काटने की योजना थी। जिससे रीढ़ की हड्डी चार हिस्सों में विभाजित कर सर्जरी की जानी थी। परिवार से सर्जरी की स्वीकृति लेकर दो चरणों में सर्जरी की गई। पहली सर्जरी 18 नवंबर को की गई। इस दौरान रीढ़ की हड्डी के बीच के हिस्से (डी-8 वर्टिब्रा से एस2 तक विशेष) विशेष स्क्रू लगाकर रीढ़ की हड्डी को फिक्स किया गया। इस सर्जरी में साढ़े तीन घंटे का समय लगा।

इसके एक सप्ताह बाद दूसरे चरण में न्यूरो मॉनिटरिंग सर्विलांस तकनीक का इस्तेमाल करके वर्टिब्रल कालम रिसेक्शन (वीसीआर) सर्जरी की गई। इस दौरान एल-1 और एल-2 वर्टिब्रल व एल-4 वट्रिब्रा के सटे हुए हिस्से को हटाकर रीढ़ की हड्डी को सीधा किया गया।

सर्जरी के बाद पहले दिन 68.8 प्रतिशत सुधार हुआ। सर्जरी के चौथे दिन वह सीधी खड़ी होने लगी और उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई। उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

उन्होंने बताया कि एक हजार में से दो बच्चों को काइफोसिस बीमारी होती है। इसका जल्दी इलाज होने से कूबड़ जैसी समस्या से बचा जा सकता है। कनिष्का की मां राधा ने बताया कि जब वह 12 वर्ष की थी तब रीढ़ में टेढ़ा होने की समस्या महसूस हुई।

**एम्स से आया सर्जरी के लिए बुलावा**

बताया कि गली के झोलाछाप को दिखाया तो उसने बताया कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। यह सोचकर किसी अस्पताल में दिखाने नहीं गई। परेशानी ज्यादा बढ़ने पर बेटी को एम्स ले गई। एक वर्ष तक कई जांचें हुईं। फिर दो वर्ष के इंतजार के बाद एक दिन एम्स से सर्जरी के लिए बुलावा आया।

वहीं, सर्जरी के बाद वह ठीक है। पैरों में अभी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन सीधा खड़ा होकर सहारे के साथ चलने लगी है। डॉक्टरों ने बताया है कि कुछ दिनों में वह बिना किसी सहारे के ठीक से चलने लगेगी।

# सच है, यह सरकार नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन है जिसने आलू मनाया है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

**भुबनेश्वर:** सरकार की नाकामी सामने आ गई है। झूठ बोलकर बा-बा को खत्म करने की कोशिश कर रही सरकार की मंशा का भांडा फूट चुका है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने नहीं बल्कि व्यापारी संघ से आलू मांगा है। सरकार ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश से 300 गांठ आलू का ऑर्डर दिया गया है जबकि आलू की कमी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं।उन्होंने यह भी बताया कि आलू की गाड़ी सोमवार को ओडिशा पहुंच जायेगी। इसे लेकर व्यापार संघ ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आलू का ऑर्डर दिया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश से आलू की कुछ खेप पहुंचीं। उत्तर प्रदेश से 70 गांठ आलू और पश्चिम बंगाल से 30 गांठ आलू जल्द ही पहुंचेंगे। आलू की कमी को देखते हुए प्रदेश व्यापारी संघ ने खुद उत्तर प्रदेश से आलू मंगवाया है। राज्य सरकार का कहना है कि सरकार द्वारा ऑर्डर किया गया वाहन कहां है? संघ से पूछा आलू की खराब बिक्री को देखते हुए ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 3 से 4 दिन के अंदर यूपी से कुछ आलू मंगाया है। आज तक 70 लेन आ जाएंगी। इसके अलावा 30 लेन पश्चिम बंगाल से आएंगी। महासचिव ने कहा- आलू की आने का शुरू हो गयी है। चिंता मत करो। कीमतें निश्चित तौर पर कम होंगी। अब अधिकतम विक्रय मूल्य 3600 रुपये होगा। आयात बढ़ेगा तो दाम घटेंगे। राज्य व्यापारी संघ के महासचिव ने कहा कि जैसे-जैसे नए आलू की कटाई होगी कीमतें धीरे-धीरे नियंत्रित होंगी।

# दिल्ली में पड़ोसी की कार में आग लगाकर भागा, पुलिस ने 600 किमी दूर से किया गिरफ्तार

दिल्ली में पार्किंग विवाद के चलते पड़ोसी की कार में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने 600 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राहुल भासी के रूप में हुई है। राहुल ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर की रात को पड़ोसी की कार में आग लगाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा है।

**नई दिल्ली।** दिल्ली पुलिस ने पार्किंग विवाद के बाद पड़ोसी की कार में आग लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली से 600 किमी दूर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पास से पकड़ा गया है। उसकी पहचान राहुल भासी (28) के रूप में हुई है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में पार्किंग विवाद पड़ोसी की कार में आग लगा दी थी। आरोपी कार में आग लगने के बाद अपनी होंडा अमेज कार से अमेठी भाग गया था। पुलिस उसे दिल्ली ले आई है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने कहा, राहुल भसीन इवेंट मैनेजमेंट का व्यवसाय करता है और अपने भाई और परिवार के साथ लाजपत नगर में रहता है। उसका अपने पड़ोसी रंजीत सिंह (48) के साथ पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था। रंजीत सांस्कृतिक संगठन 'जश्न-ए-अदब' के संस्थापक हैं।

**29 नवंबर को भी कार को पहुंचाया नुकसान**

रंजीन ने 29 नवंबर को राहुल भसीन के खिलाफ मारुति सुजुकी सियाज कार को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई थी। कार उनके घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर दिखा कि भसीन ने उनकी सियाज कार का रियर व्यू मिरर घुमाया है। उसने अपनी महिंद्रा थार को बीच सड़क पर पार्क किया और भागते हुए देखा गया।

**थिनर डालकर कार में लगाई आग**

पुलिस ने रंजीत की शिकायत के बाद कार्रवाई कर थार को जब्त कर लिया। उसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी। 30 नवंबर और 1 दिसंबर की रात आरोपी राहुल ने थिनर डालकर कार के बोनट में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पुलिस ने राहुल को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। मानव खुफिया और तकनीकी इनपुट की मदद से टीम ने रविवार को यूपी के अमेठी में उसे पकड़ लिया। आरोपी को पिछले साल भी इसी मामले में उसे पकड़ा गया था।

**शराब पीकर करता था झगड़ा**

रंजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी और उसके दोस्त अक्सर उसके और उसके परिवार के लोगों से झगड़ा करते थे। इसके अलावा राहुल शराब पीने के बाद अक्सर उसके साथ झगड़ा करता था। इसकी हर बार पुलिस से शिकायत भी कई गई और पुलिस ने कार्रवाई की।

## खत्म हुई अठखेलियाँ

●●●

दुनिया मतलब की हुई, रहा नहीं संकोच।
हो कैसे बस फायदा, यही लगी है सोच॥

●●●

औरों की जब बात हो, करते लाख बवाल।
बीती अपने आप पर, भूले सभी सवाल॥

●●●

मतलब हो तो प्यार से, पूछ रहे वह हाल।
लेकिन बातें काम की, झट से जाते टाल॥

●●●

लगी धर्म के नाम पर, बेमतलब की आग।
इक दूजे को डस रहे, अब जहरीले नाग॥

●●●

नंगों से नंगा रखे, बे-मतलब व्यवहार।
बजा-बजाकर डुगडुगी, करते नाच हज़ार॥

●●●

हर घर में कैसी लगी, ये मतलब की आग।
अपनों को ही डस रहे, बने विभीषण नाग॥

●●●

बचे कहाँ अब शेष हैं, रिश्ते थे जो ख़ास।
बस मतलब के वास्ते, डाल रहे सब घास॥

●●●

'सौरभ' डीoसीo रेट से, रिश्तों के अनुबंध।
मतलब पूरा जो हुआ, टूट गए सम्बन्ध॥

●●●

तेरी खातिर हों बुरे, नहीं बचे वे लोग।
समझ अरे तू बावरे, मतलब का संयोग॥

●●●

रिश्तों में है बेड़ियाँ, मतलब भरे लगाव।
खत्म हुई अठखेलियाँ, गायब मन से चाव॥

—डॉo सत्यवान 'सौरभ'
तितली है खामोश (दोहा संग्रह)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023